20 फरवरी, 2021 * वर्ष-30, पृष्ठ संख्या 60, अंक-2

राजस्थान सुजस

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

आयुष्मान भारत - महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना

मिट रहा मर्ज़ – बिना किसी खर्च

जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

श्रद्धासुमन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गणतन्त्र दिवस पर अमर जवान ज्योति पर पहुंचकर अमर शहीदों को याद किया। मुख्यमंत्री ने पुष्पचक्र अर्पित कर देश के लिए शहादत देने वाले सैनिकों को नमन किया।

प्रधान सम्पादक
महेन्द्र सोनी, आईएएस
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

सम्पादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप सम्पादक
आशाराम खटीक

कला
विनोद कुमार शर्मा

आवरण छाया
सुजस

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
प्रिण्ट 'ओ' लैण्ड

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय परिसर
जयपुर - 302 005
e-mail :
publication.dipr@rajasthan.gov.in
editorsujas@gmail.com
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 30 अंक : 02 फरवरी, 2021

इस अंक में

आयुष्मान भारत

05

गणतंत्र दिवस 2021

14

बजट पूर्व चर्चा

38

श्रद्धासुमन	02
सम्पादकीय	04
शहीद दिवस	26
एम. सेंड नीति	27
राष्ट्रीय महिला दिवस	44
स्वयं सहायता समूह	45
पेयजल	48
सफलता की कहानी	52
सशक्त लोकतंत्र	56
कोरोना वैक्सीन	57
वैक्सीन प्रोग्राम	58
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन	59

निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

60

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

कोरोना और टीकाकरण

08

सामयिकी

28

साक्षात्कार

46

प्रदेश का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता

राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास का कार्य कर रही है। कृषि, पशुपालन, औद्योगिक विकास, व्यापार, श्रम, रोजगार, ग्रामीण विकास, सहकारिता, नगरीय विकास, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, खाद्य सुरक्षा, आधारभूत संरचना, सूचना तकनीकी, पर्यटन, सामुदायिक सेवाओं व आधारभूत सुविधाओं के साथ सभी क्षेत्रों में त्वरित विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने विशेषत: महिलाओं, बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति–जनजाति, अन्य पिछड़ा, अल्पसंख्यक व दिव्यांग सहित किसानों, श्रमिकों व छोटे व्यापारियों के कल्याण के लिए पारदर्शी, जवाबदेह एवं संवेदनशील तरीके से कार्य करके जन विश्वास अर्जित किया है।

कोरोना प्रबंधन में राज्य को देश में एक मॉडल के रूप में पहचान मिली। वैक्सीनेशन में भी राजस्थान को मॉडल राज्य बनाये जाने के लिए राज्य सरकार मिशन के रूप में कार्य कर रही है। अब वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण कराना होगा। वैक्सीन आने के बावजूद भी कोरोना से बचाव के लिए सावधानियों का पालन करना आवश्यक है।

राज्य सरकार ने राज्य में भामाशाह योजना का स्वरूप वृहद कर आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी–राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। दस लाख से अधिक नये परिवारों को जोड़कर अब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को इस बीमा योजना के तहत 5 लाख रूपये तक की उपचार सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी। जनहित में यह महत्त्वपूर्ण पहल है। योजना के अन्तर्गत कुल प्रीमियम राशि 1 हजार 748 करोड़ रूपये में से लगभग 80 प्रतिशत राशि का राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना स्वस्थ राजस्थान के लिए सुखद प्रयास है।

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को भी राज्य सरकार प्राथमिकता दे रही है। 81 हजार 663 युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान कर दिये गये हैं और 50 हजार 865 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। साथ ही एक लाख से अधिक युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के भरसक प्रयास कर रही है।

राजस्थान सुजस के इस अंक में 72 वें गणतंत्र दिवस के आयोजनों सहित वैक्सीनेशन की प्रगति और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नये चरण से संबंधित आलेखों का समावेश किया गया है। राजस्थान सुजस, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.dipr.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(महेन्द्र सोनी)
आई.ए.एस.
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण में लाभार्थियों को मिलने वाला बीमा कवर 3 लाख 30 हजार से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दिया गया है। योजना में विभिन्न बीमारियों के नि:शुल्क इलाज के लिए पैकेज की संख्या 1401 से बढ़ाकर 1576 कर दी गई है। योजना का लाभ प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को मिलेगा।

प्रदेशवासियों को समर्पित
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन चरण

एक करोड़ 10 लाख परिवारों को मिलेगा 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस, 30 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण का शुभारम्भ किया है। इस योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले बीमा कवर को 3 लाख 30 हजार से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दिया गया है। योजना में विभिन्न बीमारियों के नि:शुल्क इलाज के लिए बीमा पैकेज की संख्या 1401 से बढ़ाकर 1576 कर दिया गया है। योजना का लाभ प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को मिलेगा।

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण के शुभारम्भ पर मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों का अच्छा स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन 'स्वास्थ्य ही व्यक्ति की असली सम्पत्ति है' की भावना के अनुरूप सरकार ने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया है। नि:शुल्क दवा, जांच योजनाओं तथा निरोगी राजस्थान अभियान के बाद अब स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से गरीब और वंचित लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट किए गए कार्यक्रम में कहा कि यह योजना एक बड़ा निवेश है। इसे आयुष्मान भारत, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा सहित दूसरे प्रदेशों की बीमा योजनाओं की खामियों और विशेषताओं के अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने केन्द्र की आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी सामाजिक आर्थिक जनगणना के चयनित परिवारों के साथ-साथ प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के लाभार्थी परिवारों को भी इस योजना में बीमा कवर उपलब्ध कराया है।

एनएफएसए के लाभार्थियों के लिए प्रीमियम की शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। चयनित परिवारों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि 1052 रूपये प्रति परिवार की 60 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है।

राजस्थान में योजना की वास्तविक प्रीमियम राशि 1662 रूपये प्रति परिवार है। राज्य सरकार चयनित परिवारों के लिए भी केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि 1052 रूपये और वास्तविक प्रीमियम राशि 1662 रूपये के अन्तर का भुगतान कर रही है।

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम लगभग 1800 करोड़ रूपये है, जिसमें से राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 1400 करोड़ रूपये और केन्द्र सरकार द्वारा 400 करोड़ रूपये का भुगतान किया जायेगा।

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां अलग-अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याएं भी अलग-अलग हैं। ऐसे में सभी को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार ने इस नई योजना के माध्यम से प्रदेश की दो-तिहाई आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया है। योजना के प्रचार-प्रसार में मीडिया सहित सभी नागरिकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने अधिकाधिक लोगों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाने की आवश्यकता जताई है, ताकि गरीब एवं वंचित बीमार व्यक्ति को समय पर 'बिना खर्च' इलाज मिल सके।

योजना में अनियमिताओं को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। योजना के सॉफ्टवेयर में अस्पताल अथवा बीमा कंपनी द्वारा गड़बड़ कर गलत लाभ लेने की स्थिति में ऑटोमेटिक अलर्ट जारी होने की व्यवस्था की गई है। एक स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट का गठन किया गया है, जो अस्पतालों द्वारा गलत क्लेम पेश किए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। योजना के लिए निजी अस्पतालों के चयन की प्रक्रिया भी बेहतर बनाई गई है।

मरीज के अस्पताल पहुंचने पर जल्द उपचार मुहैया कराने के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अस्पताल और बीमा कंपनी के सहयोग के लिए व्यवस्था की गई है। अस्पताल में मरीजों की सहायता के लिए स्वास्थ्य मार्गदर्शक तथा स्वास्थ्य मित्र भी उपलब्ध होंगे।

मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का समस्त चिकित्सकीय व्यय नि:शुल्क पैकेज में शामिल है। इस योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 के इलाज और हीमोडायलिसिस को भी जोड़ा गया है। आने वाले दिनों में पोर्टेबिलिटी का विकल्प उपलब्ध होने के बाद राजस्थान के निवासियों को दूसरे राज्य के चिन्हित अस्पतालों में भी इस योजना के तहत नि:शुल्क इलाज का लाभ उपलब्ध हो सकेगा।

राजस्थान में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना पर विजय की तरफ प्रदेश बढ़ रहा हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण में 60 प्रतिशत हैल्थकेयर वर्कर्स को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। आने वाले दिनों में देश में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी शुरू होगा और कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान देश का आदर्श राज्य बनेगा।

राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए लगातार निवेश कर सुविधाओं का विकास किया है। इस क्रम में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा और जांच योजनाएं महत्त्वपूर्ण सोपान रही हैं। अब इस स्वास्थ्य बीमा योजना के लागू होने के बाद राज्य के अन्तिम छोर तक के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन चरण

नवीन चरण की विशेषताएं

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के लाभार्थी परिवारों के सदस्य योजना में पात्र।
- योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में भी नि:शुल्क इलाज।
- सामान्य बीमारी के लिए 50 हजार और गंभीर बीमारी के लिए 4 लाख 50 हजार तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष का बीमा।
- अस्पताल में भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक के इलाज का खर्च पैकेज में शामिल।

लाभार्थी के लिए आवश्यक जानकारी

- सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थी अपनी परिवार पहचान संख्या को नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जन आधार कार्ड में दर्ज कराएं।
- जब भी अस्पताल जायें, अपना जन आधार कार्ड साथ लेकर जायें।
- अस्पताल में इलाज के दौरान सही मोबाइल नंबर दर्ज कराएं ताकि आपको बीमा वॉलेट की जानकारी एस.एम.एस. से मिल सके।
- अस्पताल से डिस्चार्ज के समय फीडबैक फॉर्म अवश्य भरें।

स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पूर्व में विभिन्न बीमारियों के 1401 पैकेज और प्रोसीजर उपलब्ध थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 1576 किया गया है। सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार रूपये तक का इलाज खर्च और गंभीर बीमारियों के लिए 4.50 लाख रूपये तक के इलाज खर्च के लिए बीमा कवर उपलब्ध है।

आदमी जब स्वस्थ होता है तो वह पूरे मनोयोग के साथ अपने व्यक्तित्व को न केवल आकार देता है बल्कि समाज में अपनी पहचान बनाने और कार्यों को करने के लिए भी संपूर्ण मनोबल के साथ जुट जाता है। किंतु जब उसका शरीर ठीक नहीं होता तो उसे चिकित्सा की आवश्यकता होती है।

किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो उसको तत्काल इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा मिलना आवश्यक है। यही वजह है कि राजस्थान के गरीब तबके के लिए महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक अभिनव पहल है। राजस्थान सरकार प्रतिबद्धता के साथ आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए चिंतित है ।

यह योजना बिना किसी शुल्क के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है। इसके दायरे में आने वाले प्रतिभागियों की जांच एवं इलाज नि:शुल्क किया जाता है और यह राशि सरकार द्वारा देय होती है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने के खर्चे, डे केयर ट्रीटमेंट, किसी भी बीमारी के बाद आगामी सेवा एवं सहायता भी शामिल है। इसमें प्रमुख रूप से प्रत्येक परिवार का 5 लाख रुपये सालाना का बीमा का प्रावधान है। आम आदमी की चिकित्सा सुविधा के लिए बहुत सारे निजी चिकित्सालयों से भी इस योजना को जोड़ा गया है ताकि मेडिकल इमरजेंसी में चिकित्सा सेवा का लाभ लोग ले सकें और त्वरित चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थी परिवारों के सदस्य योजना में पात्र हैं। इस योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पताल में पूरा इलाज नि:शुल्क किया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थी परिवारों के सदस्य योजना में पात्र हैं। इस योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पताल में पूरा इलाज नि:शुल्क किया जाएगा।

सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थी परिवार पहचान संख्या को नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जन आधार कार्ड में दर्ज कराएं। अस्पताल में इलाज के दौरान सही मोबाइल नंबर दर्ज कराया जाना आवश्यक है ताकि बीमा वॉलेट की जानकारी एसएमएस के माध्यम से मिल सके।

अस्पताल से डिस्चार्ज के समय फीडबैक फॉर्म भरना होगा। राजस्थान सरकार की यह महत्त्वपूर्ण योजना लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब तक आम आदमी स्वस्थ और सुरक्षित नहीं होगा तब तक वह समाज को अपना योगदान बेहतर स्वरूप में नहीं दे सकेगा। महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से चरणबद्ध रूप से पूरे राजस्थान में आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरीन सेवा मिल सकेगी और वे समय पर अपना उपचार करवाकर स्वस्थ एवं प्रसन्न रह सकेंगे।

30 जनवरी, 2021 से लागू महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना स्वस्थ मानव जीवन की दिशा में पहल है, जो राज्य सरकार द्वारा आम जन के प्रति सरोकार की अवधारणा को साकार कर रही है। ●

सुब्रता पाराशर

कोरोना और टीकाकरण

राज्य सरकार का बेहतरीन प्रबंधन

केंद्र सरकार ने भीलवाडा व रामगंज मॉडल की तारीफ की और यहां के प्रभारियों को कुशल प्रबंधन के लिए धन्यवाद दिया। वैक्सीन के लिए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। कोविड से आखिरी लड़ाई के लिए 16 जनवरी, 2021 का दिन महत्त्वपूर्ण रहा। इस दिन स्वयं मुख्यमंत्री ने टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया।

वर्ष 2020 कोरोना वैश्विक महामारी के लिए जाना जाता रहेगा। सूनी गलियां, डरे सहमे लोग, सुनसान सड़कें। बस, मंजिल को तलाशती आंखें। मानो रास्ते सब ठहर से गए हों। सब का एक ही प्रयास सिर्फ जीवन को बचाने की जद्दोजहद।

कोविड-19 वायरस ने जीवन को मानो कैद कर दिया हो। इस स्थिति में इस संक्रामक महामारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी करार दिया। हालांकि इस महामारी का समय रहते कारण पता लगा होता तो बेहतर कारगर उपाय किए जा सकते थे। भारत भी इसके कहर का शिकार बना।

कोविड शील्ड AZD 1222 वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका के नाम से भी जाना जाता है। जिसका जन्म एक आशा की किरण साबित हुआ। अप्रैल, 2020 में जब सारा संसार कोविड-19 से जूझ रहा था तब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा एक आशा की किरण जगाई गई और वैक्सीन बना ली गई। अमेरिका की फाइजर, रूस की स्पूतनिक तथा ब्रिटेन की फार्मा कम्पनियां भी इस दौड़ में शामिल थीं।

सभी विकसित देश इस वैक्सीन विकास की दौड़ में शामिल होते गए। फेज प्रथम में अप्रैल, 2020 के अंतिम सप्ताह में कोविड-19 का

प्रथम मानव परीक्षण प्रारंभ हुआ तथा 2 लोगों को यूरोप में वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन की प्रभाविता की जांच के लिए 1100 व्यक्तियों पर परीक्षण किया गया। ऑक्सफोर्ड के अनुसार सेवाओं में से आधे लोगों को अध्ययन हेतु मेनिनजाइटिस की उपलब्ध वैक्सीन दी गई। अन्वेषणकर्ता स्वास्थ्य स्वयंसेवियों के 18 से 55 आयु वर्ग का मार्च में बारीकी से वैक्सीन के प्रभाव का अध्ययन प्रारंभ कर दिया गया।

प्रथम परीक्षण के अध्ययनों के तुरंत बाद एसआईआई ने अक्टूबर, 2020 से वैक्सीन उत्पादन प्रारंभ कर दिया। ब्राजील में जून माह में परीक्षण प्रारंभ किए गए पर यहां कोविड-19 का प्रभाव कम होने के कारण पर्याप्त परीक्षण नहीं किए जा सके। ब्रिटेन में क्रिसमस पर वैक्सीन दिए जाने की घोषणा की गई थी। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन द्वारा एसआईआई को वैक्सीन निर्माण की अनुमति दी गई और आधार पूनावाला ने घोषणा की कि उत्पादन पर उत्पादित वैक्सीन का 50 प्रतिशत हिस्सा भारत में उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा।

वैक्सीन का भारत और अन्य देशों में ट्रायल सितंबर, 2020 में प्रारंभ हुआ। कोविड वैक्सीन की प्रभाविता 62 प्रतिशत पाई गई। जिसकी प्रभाविता को 90 प्रतिशत करने के लिए चिकित्सकों ने कोविड वैक्सीन के छोटे द्वितीय डोज देने की सलाह दी। नव वर्ष 2021 में भारत बायोटेक के को- वैक्सीन के ट्रायल व सकारात्मक परिणाम आने प्रारंभ हो गए।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल प्रबंधन का ही परिणाम रहा कि राज्य ने कोरोना का डटकर मुकाबला किया। सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान में लगाया गया। इस दौरान ट्रेनों और बसों के जरिये लोगों को नि:शुल्क अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। कोरोना काल में समय-समय पर आवश्यक एडवाइजरी जारी की गयी। संक्रमण से बचने के लिए नियमित रूप से लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने सहित अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल की निरंतर पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश की जनता को प्रेरित करते रहे। जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इस हेतु अतिरिक्त प्रयास किये गए।

प्रदेश में गरीब, किसान, मजदूर भूखा ना सोये और संक्रमण से भी बचा रहे इस हेतु प्रदेश स्तर पर पर्याप्त प्रयास किए गए। कोरोना प्रबंधन के चलते भीलवाडा व जयपुर का रामगंज देश में चर्चा का विषय बना। केंद्र सरकार ने भी भीलवाडा व रामगंज मॉडल की तारीफ की और यहां के प्रभारियों को कुशल प्रबंधन के लिए धन्यवाद दिया। वैक्सीन के लिए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सभी वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कीं। कोविड से आखिरी लड़ाई के लिए 16 जनवरी, 2021 का दिन महत्वपूर्ण रहा। इस दिन स्वयं मुख्यमंत्री ने टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया।

प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर्स के लिए टीकाकरण की शुरुआत का निर्णय लिया गया। यह निश्चय किया गया की टीकाकरण के लिए

पंजीकृत मोबाइल पर दिनांक, समय एवं स्थान का सन्देश आने पर ही पहुंचना होगा। टीकाकरण सप्ताह में 4 दिन होगा। सामान्य मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इस हेतु भी पूरा ध्यान रखकर टीकाकरण की कार्य योजना बनाई गयी। मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो। सभी प्रदेशवासी स्वस्थ रहें।

कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को निरन्तर जागरूक करने की आवश्यकता

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हेल्थ केयर वर्कर्स के उत्साह के साथ आगे आकर वैक्सीन लगवाने की प्रशंसा की है। वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह कि भ्रांति न फैले, इसके लिए लोगों को निरन्तर जागरूक किया जाए। वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या भी आवश्यकतानुरूप बढ़ाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैक्सीनेशन अभियान की प्रगति की निरन्तर समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स एवं आमजन का आह्वान किया कि वे टीकाकरण करवाएं और किसी भी तरह की भ्रांति से बचें। उन्होंने भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए प्रदेश में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को तय समय में पूरा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूरोप सहित विश्व के कुछ देशों में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए हमें पूरी तरह सावचेत रहने की जरूरत है। हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन होने पर वे आगे आने वाली किसी भी चुनौती का मुकाबला पूरे आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे और कोरोना से प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा का अपना दायित्व बखूबी निभा सकेंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने जयपुर, दौसा एवं गंगानगर सहित जिन जिलों में वैक्सीनेशन का प्रतिशत कम है, वहां के कलक्टर, सीएमएचओ एवं विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ वीसी कर वैक्सीनेशन को गति देने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।

वैक्सीनेशन के सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन

शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन ने वैक्सीनेशन की प्रगति एवं आगे के लक्ष्य के बारे में बताया कि वैक्सीनेशन के राष्ट्रीय औसत की तुलना में राजस्थान आगे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए विस्तृत मूल्यांकन में भी राजस्थान ने टीकाकरण के सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। राजस्थान में 25 जनवरी तक 1 लाख 61 हजार 116 स्वास्थ्यकर्मियों का वैक्सीनेशन किया गया।

राजस्थान में अभी तक 95.72 प्रतिशत वैक्सीन का उपयोग हो रहा है और वैक्सीन का वेस्टेज प्रतिशत मात्र 4.28 फीसदी रहा है। पूरे देश में 22 प्रतिशत हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन के मुकाबले राजस्थान में 31.35 प्रतिशत का टीकाकरण किया गया है। यह राष्ट्रीय औसत से करीब 10 प्रतिशत अधिक है।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी ने कहा कि अभी तक जिन हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन हुआ है, उनमें से सभी आयु वर्गों में साइड इफेक्ट्स जीरो रहा है। आरयूएचएस के कुलपति डॉ. राजाबाबू पंवार, विशेषज्ञ डॉ. वीरेन्द्र सिंह, डॉ. अशोक अग्रवाल, डॉ. एम एल गुप्ता, डॉ. रमन शर्मा, डॉ. रामबाबू शर्मा, डॉ. अमिता कश्यप सहित अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों ने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सुझाव दिए।

हेल्थवर्कर्स का शत-प्रतिशत टीकाकरण जरूरी

टीकाकरण के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राजस्थान आगे है और अब तक वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए विस्तृत मूल्यांकन में राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जो टीकाकरण के सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के कारण ग्रीन कैटेगरी में है। भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या बढ़ाकर प्रथम चरण का टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या 167 से बढ़ाकर 350 करने और आवश्यकता के अनुरूप इनकी संख्या

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हेल्थ केयर वर्कर्स के उत्साह के साथ आगे आकर वैक्सीन लगवाने की प्रशंसा की हैं। वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह कि भ्रांति न फैले, इसके लिए लोगों को निरन्तर जागरूक किया जाए। वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या भी आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा रही हैं।

और बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स के जल्द टीकाकरण के लिए सप्ताह में टीकाकरण दिवस की संख्या बढ़ाएं। साथ ही, निजी अस्पतालों में भी साइट्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार कोरोना का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में हमारे हेल्थ वर्कर्स का शत-प्रतिशत टीकाकरण जल्द से जल्द होना जरूरी है ताकि भविष्य में कोरोना की नयी लहर आए तो वे पूरी सुरक्षा एवं आत्मविश्वास के साथ प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा कर सकें, साथ ही अगले चरणों के टीकाकरण के लिए भी तैयार हो सकें।

अभियान को गति देने के लिए व्यवस्थाओं का विकेन्द्रीकरण

श्री गहलोत ने कहा कि देश में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में केन्द्र सरकार को इस अभियान को गति देने के लिए इसकी व्यवस्थाओं तथा प्रबंधन का अधिक विकेन्द्रीकरण करना चाहिए ताकि राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप टीकाकरण के लक्ष्य को जल्द हासिल कर सकें।

स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक, निजी संस्थानों का आमुखीकरण, वैक्सीनेशन टीम और मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षण सहित अन्य मानकों पर राजस्थान की परफोरमेंस अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। राजस्थान सभी मानकों पर ग्रीन कैटेगरी वाला राज्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में किसी तरह की भ्रांति न रहे। लोगों को मीडिया का सहयोग लेकर निरन्तर जागरूक किया जाए। कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीन की एक-एक बूंद कीमती है। वैक्सीनेशन सेन्टर्स पर प्रबंधन इस प्रकार से हो कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से तैयार वैक्सीन का अधिकतम सदुपयोग हो सके। श्री गहलोत ने कहा कि लोग पूरे विश्वास के साथ टीकाकरण करवाएं और किसी भी तरह की भ्रांति से बचें।

प्रदेश में मात्र 3.40 प्रतिशत ही वैक्सीन वेस्टेज

भारत सरकार की गाइडलाइन में विभिन्न कारणों से वैक्सीन की 90 प्रतिशत मात्रा के उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन राजस्थान में अभी तक 96.59 प्रतिशत वैक्सीन का उपयोग किया है। प्रदेश में वैक्सीन का वेस्टेज प्रतिशत मात्र 3.40 रहा है। इसे और कम करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। प्रदेश में प्रथम तीन दिन में 501 सेशन साइट्स पर 32 हजार 379 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया है। यह राष्ट्रीय औसत से करीब 9 प्रतिशत अधिक है।

डब्ल्यूएचओ के सभी मानकों पर राजस्थान ग्रीन कैटेगरी में

विश्व स्वास्थ्य संगठन के राजस्थान प्रमुख डॉ. राकेश ने प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि प्रदेश में टीकाकरण की 67 प्रतिशत साइट्स का निरीक्षण किया गया है। इसमें स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक, निजी संस्थानों का आमुखीकरण, वैक्सीनेशन टीम और मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षण सहित अन्य मानकों पर राजस्थान की परफोरमेंस अन्य राज्यों से काफी बेहतर रही है। राजस्थान सभी मानकों पर ग्रीन कैटेगरी वाला राज्य है।

संक्रमण से बचाव के लिए अभी भी सतर्कता आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार कमी आने और स्थिति के नियंत्रण में रहने के दृष्टिगत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों और कॉलेजों में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना की शर्तों के साथ शैक्षिक संस्थानों को खोलने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही, सभी सिनेमा हॉल, थियेटर और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेंगे। सामाजिक एवं अन्य आयोजनों में 200 लोगों तक उपस्थिति की छूट दी गई है।

मुख्यमंत्री ने टीकाकरण अभियान की समीक्षा बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए। पटाखों की दुकानों तथा विभिन्न धर्मों के मेलों के आयोजन के विषय में पूर्व में लगाए गए प्रतिबन्धों में शिथिलता देने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार करने का भी निर्णय लिया गया, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है।

श्री गहलोत ने अधिकारियों को स्कूलों-कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ने पर संक्रमण को रोकने के लिए प्रोटोकॉल की पालना के प्रति अधिक सजग रहने के निर्देश दिए। स्कूलों को कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की तरह कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए भी 50 प्रतिशत उपस्थिति सहित हेल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करने की शर्त के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, कॉलेजों के लिए भी अन्तिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के सम्बन्ध में पूर्व में लागू 50 प्रतिशत उपस्थिति सहित अन्य शर्तें प्रथम एवं द्वितीय वर्ष विद्यार्थियों के लिए लागू होंगी।

उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के लिए जारी दिशा-निर्देशों (एसओपी) के अनुरूप ही प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक मेलों के लिए नए एसओपी जारी करने के निर्देश दिए। शादी-विवाह समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए जिला कलक्टर को पूर्व सूचना देने तथा सभी हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना की शर्त के साथ अब ऐसे आयोजनों में आगन्तुकों की उपस्थिति 200 व्यक्ति तक रह सकेगी।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान में हेल्थकेयर वर्कर्स के कोविड टीकाकरण अभियान में और अधिक तेजी लाकर लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में टीकाकरण अभियान का संचालन बेहतरीन है। कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और देशभर में लाखों हेल्थकेयर वर्कर्स को लगाई जा चुकी है। प्रदेश में टीकाकरण के लक्ष्य को जल्द हासिल करने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। टीकाकरण के दूसरे चरण के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूचियों सहित सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के भी निर्देश दिए।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार कमी आने और स्थिति के नियंत्रण में रहने के दृष्टिगत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों और कॉलेजों को स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना की शर्तों के साथ खोल दिये गये हैं। साथ ही, सिनेमा हॉल, थियेटर और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। राजस्थान में पॉजिटिविटी दर मात्र 5.44 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। साथ ही, रिकवरी रेट 98.42 प्रतिशत पहुंच गई है

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी ने बताया कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण लगभग अपने अन्तिम समय में है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) के कोविड अस्पताल में अब कोरोना से किसी की मृत्यु के कोई समाचार नहीं हैं। अस्पताल में केवल 5 प्रतिशत बेड पर ही मरीज हैं। वैक्सीनेशन अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है और प्रदेश में वैक्सीन का साइड-इफेक्ट भी नहीं देखा गया है। विभिन्न अस्पतालों में नॉन-कोविड स्वास्थ्य सेवाएं भी गति पकड़ रही हैं। इन सभी समन्वित प्रयासों एवं राज्य सरकार के बेहतरीन प्रबंधन के स्वरुप अब कोरोना महामारी पर जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। ●

प्रकाश चंद्र शर्मा

गणतंत्र दिवस 2021

हर्षोल्लास के साथ मनाया

72 वां गणतंत्र दिवस

उत्साह, उमंग और भव्यता के साथ मनाया प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस

प्रदेश में 72 वां गणतंत्र दिवस समारोह सभी जिला मुख्यालयों पर हर्षोल्लास के साथ समारोहपूर्वक मनाया गया। जिला मुख्यालयों पर आयोजित समारोह में मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर द्वारा ध्वजारोहण करने के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली गई तथा स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये।

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 72 वें गणतन्त्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राज्यपाल

श्री मिश्र ने परेड का निरीक्षण किया और राज्यस्तरीय समारोह के साक्षी बने अतिथियों और जनसमूह का अभिवादन स्वीकार किया।

राज्यपाल श्री मिश्र ने सलामी गार्ड द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी भी उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में हाडीरानी महिला बटालियन, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, एसडीआरएफ, जीआरपी, चौदहवीं बटालियन आरएसी, बॉर्डर होमगार्ड, अरबन होमगार्ड, कारागृह आदि की बटालियन ने परेड में हिस्सा लिया। परेड का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी सुश्री रंजिता शर्मा ने किया।

गणतंत्र दिवस के आयोजन में हल्की सर्दी और गुनगुनी धूप में लोककलाकारों, विद्यालयी बच्चों और पुलिस बैंड की रंगारंग

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। स्टेडियम में जब मांगणियार कलाकारों का प्रवेश हुआ तो पूरा माहौल लोक संस्कृति से सराबोर हो गया। इन कलाकारों ने चंग की थाप के साथ गैर नृत्य, चरी नृत्य, घूमर आदि की मनोहारी प्रस्तुतियां दीं। लोक कलाकारों द्वारा प्रख्यात रंग निर्देशक श्री भानु भारती के निर्देशन में राजस्थान की नृत्य

और गायन की परम्पराओं को स्टेडियम में जीवंत किया गया। वंदे मातरम्, पधारो म्हारे देश, धरती धोरां री आदि प्रस्तुतियां समारोह को गौरव प्रदान कर रही थीं।

राजस्थान पुलिस के जवानों ने मोटरसाइकिल एवं घुड़सवारी के अद्भुत करतब दिखा कर शौर्य, साहस एवं संतुलन की मिसाल पेश की। बैंड मास्टर हवलदार जगजीत सिंह के नेतृत्व में सेना बैंड एवं श्री नरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में सेन्ट्रल पुलिस बैंड ने देशभक्तिपूर्ण गीतों की धुनों पर समवेत स्वर में प्रस्तुतियां दीं। समारोह का संचालन श्री अरुण जोशी व डॉ. ज्योति जोशी ने किया।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ की ओर से शासन सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में झंडारोहण किया।

श्री गहलोत ने सचिवालय स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, वरिष्ठ अधिकारी तथा सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों सहित सचिवालय सेवा के कार्मिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर भी झण्डारोहण किया। श्री गहलोत को आर.ए.सी. की टुकड़ी ने सलामी दी। मुख्यमंत्री ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी।

संविधान की मूल भावना को आत्मसात् करने की प्रेरणा देता है गणतंत्र दिवस

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमें संविधान की मूल भावना को आत्मसात् करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जैसे मूल्यों को अपनाकर ही हम इस देश को एकता के सूत्र में बांधे रख सकते हैं।

श्री गहलोत ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन हम देश के लिए शहीद हुए उन हजारों सेनानियों को याद करते हैं, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। हमारे महान नेताओं ने देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि संविधान की पालना करते हुए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी शहीद हो गए, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों को कामयाब नहीं होने दिया। आज हमें इसी भावना के साथ लोकतंत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है।

श्री गहलोत ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के लम्बे दौर का राज्य सरकार ने हर वर्ग को साथ लेकर सफलतापूर्वक सामना किया है। हमारे कुशल प्रबंधन की देशभर में सराहना हो रही है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और इसके टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो गया है, लेकिन हमें अब भी पूरी सजगता और सतर्कता के साथ रहना होगा। हमारी लापरवाही से संक्रमण का खतरा फिर बढ़ सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेशवासियों को गुड गवर्नेंस मिले, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हों और राजस्थान उन्नति के शिखर पर पहुंचे।

> गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमें संविधान की मूल भावना को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। लोकतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जैसे मूल्यों को अपनाकर ही हम इस देश को एकता के सूत्र में बांधे रख सकते हैं।

अजमेर

अजमेर जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस समारोह पटेल मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह में संभागीय आयुक्त डॉ. वीणा प्रधान ने ध्वजारोहण कर मार्चपास्ट की सलामी ली।

जिला स्तरीय समारोह में शिक्षा विभाग द्वारा पारंपरिक लोक रचना घूमर पर समूह नृत्य प्रस्तुत किया गया। श्री अशोक शर्मा के दल ने कोरोना जागरुकता से जुड़े गीत भाग 'कोरोना म्हारे भारत देश सूं...' पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया।

समारोह के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा मनमोहक व्यायाम प्रदर्शन किया गया। इसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षकों द्वारा श्री जसवंत सिंह के नेतृत्व में व्यायाम प्रदर्शन किया। इसके साथ-साथ एक दल ने विभिन्न योग आसन कर स्वास्थ्य का संदेश दिया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के. के. सोनी एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एस. जोधा के निर्देशन में कोरोना जागरुकता झांकी प्रदर्शित की। इसमें कोरोना के बचाव एवं उपचार की पूरी प्रक्रिया बताई गई। सेनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने एवं सावधानी बरतने का संदेश दिया गया। कोरोना का समुचित उपचार किया जा सकता है। सरकार द्वारा चलाए गए कोरोना टीकाकरण अभियान के बारे में भी प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई। नगर निगम के द्वारा स्वच्छता पर आधारित झांकी प्रदर्शित की गई।

डूंगरपुर

राष्ट्रीय पर्व 72 वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पूरे जिले भर में हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ गरिमामय रूप से कोविड एडवाइजरी एवं गाइडलाइन की पालना करते हुए मनाया गया।

जिला स्तर पर स्थानीय लक्ष्मण मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि डूंगरपुर जिला कलक्टर, श्री सुरेश कुमार ओला ने ध्वजारोहण किया एवं मार्चपास्ट कर सलामी ली। इस दौरान पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। ध्वजारोहण के पश्चात् मुख्य अतिथि द्वारा मार्चपास्ट परेड का निरीक्षण कर सलामी ली गई।

उदयपुर

उदयपुर संभाग मुख्यालय पर राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 2021 का मुख्य समारोह गांधी ग्राउण्ड में उत्साह एवं सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी एवं परिवहन व सैनिक कल्याण मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं।

विधानसभा में झण्डारोहण

कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जागरुकता पर आधारित झांकी निकाली गई, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए किए गये प्रयासों एवं वैक्सीनेशन प्रक्रिया को दर्शाया गया।

समारोह में कोरोना जागरुकता के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए गए ऑडियो जिंगल्स तथा जिला प्रशासन उदयपुर द्वारा तैयार करवाए गए मेवाड़ी और हिंदी ऑडियो संदेशों का भी लगातार प्रसारण किया गया।

सवाईमाधोपुर

गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित जिलास्तरीय समारोह में उद्योग एवं राजकीय उपक्रम विभाग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने झंडारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। झंडारोहण के साथ ही पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान का वादन किया गया। मुख्य अतिथि श्री परसादी लाल मीणा ने खुली जिप्सी में सवार होकर मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बैंड की धुन के साथ पुलिस एवं आरएसी के जवानों ने मार्चपास्ट किया।

करौली

जिले भर में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिलास्तरीय मुख्य समारोह मुंशी त्रिलोकचन्द माथुर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां जिला कलक्टर श्री सिद्धार्थ सिहाग ने ध्वजारोहण कर मार्चपास्ट की सलामी ली।

शारीरिक शिक्षकों द्वारा शारीरिक व्यायाम प्रदर्शित किये गये। गणतंत्र दिवस समारोह के संपूर्ण कार्यक्रम के तहत सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क सहित अन्य कोरोना बचाव के नियमों की पूर्ण रूप से पालना भी की गई। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा प्रगति परक झांकियां निकाली गई।

जोधपुर

उप मुख्य सचेतक श्री महेन्द्र चौधरी ने गणतंत्र दिवस पर जोधपुर के उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंनें खुली जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया तथा परेड कमाण्डर श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्चपास्ट की सलामी ली।

श्री चौधरी ने इस अवसर पर नागरिकों को सम्बोधित करते हुए 72 वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी तथा कहा कि संविधान में बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जैसे महान राष्ट्र निर्माताओं के सपने और संकल्प शामिल हैं। इस संविधान की रोशनी में हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य को हर दिन मजबूत बनाने के लिए देश का हर नागरिक समर्पित है।

समारोह में आरएसी, राजस्थान पुलिस, महिला पुलिस, पुरुष व महिला होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट गाइड पुरुष व महिला, ग्रामीण पुलिस तथा होमगार्ड की टुकड़ियों द्वारा आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत की गईं। समारोह में जेडीए, नगर निगम, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि उद्यान, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, यातायात एवं शिक्षा विभाग द्वारा झांकियां भी निकाली गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की झांकी को प्रथम स्थान, महिला एवं बाल विकास की झांकी को द्वितीय, जेडीए को तृतीय तथा ट्रैफिक पुलिस की झांकी को चौथा स्थान मिला। समारोह में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमेन श्री वैभव गहलोत उपस्थित थे।

जालोर

72 वां गणतंत्र दिवस समारोह जालोर जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह शाह पूंजाजी गेनाजी स्टेडियम में सम्पन्न हुआ, जहां पर राज्य के वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री सुखराम विश्नोई

राजस्थान विधानसभा

ने ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारम्भ किया। राज्य के वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री सुखराम विश्नोई ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया तथा परेड कमाण्डर छत्तर सिंह देवड़ा के नेतृत्व में मार्च पास्ट की सलामी ली।

मुख्य समारोह में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री सुखराम विश्नोई ने गणतंत्र दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी की इस संकट भरी घड़ी में राज्य सरकार द्वारा आमजन की पीड़ा को समझते हुए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये जाकर राहत पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के कल्याण एवं विकास कार्यो के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने विगत दो वर्षो में जालोर जिले में किये गये विकास कार्यो पर संक्षिप्त प्रकाश भी डाला। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रारम्भ हो चुका है तथा अपनी बारी आने पर सभी को वैक्सीन अवश्य लगवानी है।

प्रतापगढ़

72 वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह जिला मुख्यालय पर सुखाड़िया स्टेडियम में आयोजित हुआ। जिला कलक्टर ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली।

सिरोही

जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2021 उमंग और उत्साह से मनाया गया। अरविंद पेवेलियन में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। झांकियों में प्रथम कृषि विभाग, द्वितीय शिक्षा विभाग एवं तृतीय स्थान चिकित्सा विभाग ने प्राप्त किया जिन्हें सम्मानित किया गया।

अलवर

स्थानीय इन्दिरा गांधी स्टेडियम पर जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में श्रम राज्य मंत्री ने नागरिकों को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे उत्कृष्ट संविधान के कारण ही भारत वर्ष विश्व में सबसे मजबूत गणराज्य के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता ही हमारी पहचान है, इसको कायम रखने का दायित्व हम सबका है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश उतरोत्तर वृद्धि कर रहा है जिसमें प्रत्येक नागरिक की अहम भूमिका है। हम सब संकल्प लें कि हमारा देश नई ऊंचाइयों को छुए इसके लिए अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन भी राष्ट्रहित में करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार देश के समस्त नागरिकों ने एक-दूसरे की मदद की, वह पूरी दुनिया के लिए यह हमारी अनेकता में एकता की मिसाल रही। उन्होंने गणतंत्र के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए।

सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक झांकियों में प्रथम स्थान पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को रनिंग शील्ड व द्वितीय स्थान पर महिला अधिकारिता विभाग तथा तृतीय स्थान पर समसा (शिक्षा विभाग) की झांकी को प्रतीक स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान किये गये। समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया।

कोटा

जिले भर में 72 वां गणतंत्र दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह महाराव उम्मेदसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने ध्वजारोहण किया।

इस अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम का सौंदर्यकरण कार्य एवं खेल सुविधाओं में विस्तार से स्थानीय खिलाड़ियों को लाभ मिलने के साथ-साथ प्रदेशभर के खिलाड़ियों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। उन्होंने इस अवसर पर कोरोना के कारण लम्बे समय से बंद रही सिटी बसों को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया।

झुंझुनूं

72 वां गणतंत्र दिवस समारोह, स्वर्ण जयंती स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। तकनीकी शिक्षा, राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने ध्वजारोहण किया। राज्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली।

डॉ. गर्ग ने गणतंत्र दिवस की बधाई एवं वीरांगनाओं को सलाम करते हुए कहा कि झुंझुनूं जिले की माताओं का अपने लाड़ले बेटों को भारतीय सेना में भेजने का जो जज्बा है, वो काबिले तारीफ है। भारतीय सेनाओं में जिले को सैनिक भागीदारी का गौरव प्राप्त है। भारतीय सेना में जिले के सैनिकों ने सेवाएँ दी है।

प्रत्येक युद्ध एवं ऑपरेशन में झुंझुनूं के जांबाज सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने साहस को दिखाते हुए अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसके साथ ही यहां के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी स्वाधीनता संग्राम में बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

राजसमंद

जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यालय के राजकीय श्रीबाल कृष्ण विद्याभवन उ.मा.विद्यालय के मैदान में ध्वजारोहण किया और सलामी ली। पुलिस बैण्ड ने राष्ट्रगान की धुन बजाई।

दौसा

गणतन्त्र दिवस पर जिला स्तरीय समारोह राजेश पायलट स्टेडियम के प्रागंण में समारोहपूर्वक मनाया गया। समारोह में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने ध्वजारोहण किया तथा परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली।

जिलास्तरीय समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने देश की सीमा पर शहीद हुए सपूतों की वीरागंनाओं एवं माताओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि गांव, गरीब व किसानों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।

आमजन को समय पर आवश्यक सुविधाये उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आमजन के जीवन को बचाने के लिए जो कार्य किए हैं, उनकी भारत मे हीं नही बल्कि विदेशों में भी चर्चा हो रही है।

समारोह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से बचाव एवं वेक्सीनेशन के बारे में, स्वच्छता की ओर से तथा बेटी बचाओ बेटी पढाओ सहित अन्य विभागों की ओर से झांकियों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन किया गया।

बीकानेर

72 वां गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह डॉ.करणीसिंह स्टेडियम में उल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी.कल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने शान्ति के दूत सफेद कपोत और रंगबिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े।

इस पावन अवसर पर परेड में दसवीं तथा थर्ड आरएसी की प्लाटून, राजस्थान पुलिस की महिला एवं पुरूष प्लाटून, अरबन होमगार्डस तथा महारानी कॉलेज की एन.सी.सी. की टुकड़ी ने भाग लिया। शारीरिक शिक्षकों ने व्यायाम और योगा का प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री डॉ.कल्ला ने कहा कि हर साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संसद में भारत के संविधान के लागू होते ही हमारा देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य बना। उन्होंने कहा कि देश के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज देश अपना 72 वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे संविधान में समानता, एकता और धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है। उन्होंने आह्वान किया कि देश को बेरोजगारी व मंहगाई से मुक्त करवाने तथा सभी को स्वावलंबी बनाने की दिशा में मिलजुलकर हम आगे बढ़ें। उन्होंने देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का स्मरण किया।

बूंदी

72 वां गणतंत्र दिवस जिले में गरिमामय माहौल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला कलक्टर ने खेल संकुल में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद गणतंत्र दिवस की विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया ।

मुख्य समारोह खेल संकुल में प्रातः 9 बजे आरंभ हुआ। यहां जिला कलक्टर ने ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया।

भरतपुर

72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित जिलास्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि

राजस्थान शासन सचिवालय

सरकारी मुख्य सचेतक एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली।

इस अवसर मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने अपने उद्‌बोधन में भरतपुरवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनां देते हुए कहा कि अनेकों शहीदों की शहादत के बलबूते हमें यह आजादी मिली है।

समारोह में चिकित्सा विभाग द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी चिकित्सकीय गाइडलाइन की पालना एवं कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में झांकी प्रस्तुत की गयी। जिला प्रभारी मंत्री डॉ. महेश जोशी एवं अतिथियों ने जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा प्रकाशित ''सशक्त नारी सशक्त समाज'' नामक पुस्तिका का विमोचन किया।

चूरू

जिले में गणतंत्र दिवस कोविड प्रोटोकॉल एवं सोशल डिस्टेंसिंग के बीच हर्ष और गरिमा के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन मैदान में हुए जिलास्तरीय समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने ध्वजारोहण किया।

इस मौके पर प्रभारी मंत्री श्री भाटी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए महात्मा गांधी, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. अब्दुल कलाम आजाद, डॉ भीमराव अम्बेडकर, पं. जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल आदि महापुरुषों को नमन किया तथा कहा कि देश को आजाद कराने के लिए आजादी के योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर कल के लिए आज समर्पित करने वाले वीर योद्धाओं को नमन किया।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राज्य में सामूहिक प्रयासों से कोरोना से संघर्ष कर देश में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की सराहना करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ धर्मगुरुओं, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन, चिकित्साकर्मी, जनप्रतिनिधियों एवं एनसीसी स्काउड गाइड्स एवं सफाई कर्मियों सहित नागरिकों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

बाड़मेर

गणतन्त्र दिवस का जिलास्तरीय समारोह आदर्श स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्व, उप निवेशन, कृषि, सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री श्री हरीश चौधरी ने प्रातः ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली।

राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने 72 वें गणतन्त्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि आज ही के दिन हमने देश के संविधान को अंगीकृत किया था। आज का दिन हमें लोकतांत्रिक आजादी दिलाने वालों को याद करने का है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं की कल्पना के अनुरूप देश चले और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 हमारे लिए कोरोना महामारी एवं टिड्डी प्रकोप जैसी आपदाओं के कारण चुनौतीपूर्ण रहा।

कोरोना एवं टिड्डी प्रकोप के दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा बेहतर प्रबन्धन कर लोगों को राहत पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कोरोना काल में करीब 150 वीडियों कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रदेश में किए गए चिकित्सा प्रबन्धों सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना के सन्दर्भ में जमीनी स्तर पर सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका एएनएम एवं आशा सहयोगिनियों की रही, जिन्हें ऐतिहासिक कार्य के लिए बधाई।

सीकर

72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय जिला स्टेडियम पर

सम्पन्न जिलास्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में शिक्षा, पर्यटन एवं देवस्थान राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण करने के पश्चात परेड का निरीक्षण कर संयुक्त मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उन्होंने शहीद वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।

बांसवाड़ा

गणतंत्र दिवस जिले में उत्साह एवं सादगी के साथ मनाया गया। जिलास्तरीय मुख्य समारोह शहर के कुशलबाग मैदान में आयोजित हुआ जिसमें प्रदेश के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के राज्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह बामनिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पार्षदगणों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि श्री अर्जुन सिंह बामनिया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद परेड में शामिल टुकड़ियों का निरीक्षण किया तथा परेड कमाण्डर आरआई राजेश पंचाल के नेतृत्व में सलामी मंच से मार्चपास्ट की सलामी ली।

मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह बामनिया ने कहा कि गणतंत्र दिवस के इस खुशी के मौके पर भक्ति, त्याग और तपस्या की प्रतीक वागड़धरा को नमन करते हुए सभी का तहेदिल से स्वागत, वन्दन एवं अभिनन्दन करता हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के अनुभवों को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रदेश को हर दृष्टि से विकसित एवं समृद्धशाली बनाने की उनकी मंशा के अनुरूप राजस्थान आज जनकल्याण के क्षेत्र में अलग ही पहचान कायम करने लगा है। इस संकट के समय में राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आमजन को राहत प्रदान करने के उपाय सुनिश्चित किये हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कार्य भी राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ प्रारंभ किया गया है।

राज्य सरकार के जनघोषणा पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किये गये वादों में से दो साल की अल्प अवधि में पचास प्रतिशत से अधिक को लागू किया गया है जो विकास एवं संकल्पबद्धता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि जनजाति के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को प्रशासनिक सेवाओं (आईएएस, आरएएस) की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग सेन्टर दिल्ली, जयपुर, जोधपुर में निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए विभाग द्वारा आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कुशलबाग मैदान में आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोह में कोरोना थीम पर गीत 'संकट में संयम से हमने काटी लम्बी रात, सबके सद्कर्मों से मिली है वैक्सीन की सौगात' को सराहा गया।

हनुमानगढ़

72 वां गणतंत्र दिवस जिले में समारोह पूर्वक मनाया गया। जिलास्तरीय समारोह जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि जिला कलक्टर ने सुबह ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया।

भीलवाड़ा

जिला मुख्यालय पर 72वें गणतंत्र दिवस का जिलास्तरीय समारोह स्थानीय सुखाड़िया स्टेडियम पर देशभक्तिपूर्ण माहौल में हर्षोल्लासपूर्वक आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलक्टर ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने मार्चपास्ट की सलामी ली तथा परेड का निरीक्षण किया।

जैसलमेर

गणतंत्र दिवस जैसलमेर जिले में हर्षोल्लापूर्वक मनाया गया। जिलास्तरीय मुख्य समारोह परम्परागत रूप से शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में आयोजत हुआ। मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक मामलात, मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया व मार्चपास्ट की सलामी ली। समारोह में बैण्ड धुन प्रसारण, देशभक्तिपूर्ण मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकी प्रदर्शन आदि के कार्यक्रम हुए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और झांकी में कोरोना से बचाव व रोकथाम के संदेशों तथा वैक्सीनेशन गतिविधियों के बारे में भी संदेश संवाहित किए गए। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों ने जन समूह का मन मोह लिया। इनमें नेहरू युवा केन्द्र के कलाकारों ने देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम पेश किया। पर्यटन विभाग की ओर से लोक कलाकारों ने कोरोना से बचाव का संदेश देने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुति दी और लोक गीत तथा लोक वाद्य संगीत से स्वर लहरियों का जादू बिखेरा गया।

धौलपुर

72वां गणतन्त्र दिवस जिले में समारोह पूर्वक और हर्षोल्लास से मनाया गया। जिलास्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित आरएसी परेड ग्राउण्ड पर किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि गृह रक्षा राज्य मंत्री श्री भजन लाल जाटव ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली एवं परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने परेड में शामिल राजस्थान पुलिस, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान गृह रक्षा दल की टुकड़ियों का निरीक्षण किया।

पाली

72 वां गणतंत्र दिवस जिले में धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया

गया। जिला मुख्यालय स्थित बांगड़ स्टेडियम में हुए जिलास्तरीय मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलक्टर ने ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण कर मार्चपास्ट की सलामी ली।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं पोषण एवं महिला सुरक्षा, वन स्टाप सेंटर, कृषि विभाग की मृदा जांच योजनाओं, डेयरी की शुद्ध के लिए युद्ध, जिला उद्योग केन्द्र सीईटीपी फाउण्डेशन की औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोरोना वैक्सीनेशन, शिक्षा विभाग की बालिका शिक्षा एवं स्माइल प्रोजेक्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की नवजीवन योजना, जल संग्रहण व भू-संरक्षण विभाग की राजीव गांधी जल संचय योजना, जिला परिषद की विभिन्न योजनाओं की झांकी, नगर परिषद् की स्वच्छ सर्वेक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की तकनीकी प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिला निर्वाचन की स्वीप गतिविधि, ई- मतदाता पहचान पत्र, परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा की झांकी के साथ सड़क सुरक्षा, नुक्कड नाटक एवं शपथ का कार्यक्रम हुआ।

झालावाड़

72वें गणतंत्र दिवस पर जिला कलक्टर द्वारा पुलिस परेड ग्राउण्ड श्री जी मेहमी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया गया।

मुख्य समारोह में जिला कलक्टर द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई तथा परेड का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने झालावाड़वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए वैक्सीनेशन के बाद भी सतर्कता व सजगता बरतें तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान में जिला प्रशासन का सहयोग करें।

बारां

जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में उमंग, उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि खान मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। गणतंत्र दिवस समारोह कोरोना महामारी के मध्यनजर स्वास्थ्य मानकों की पालना के साथ मनाया गया।

टोंक

जिले में 72 वां गणतन्त्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ गरिमामय ढंग से मनाया गया। समारोह में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से कोरोना से बचाव एवं वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता संदेश भी दिया गया। मुख्य समारोह खेल स्टेडियम में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने ध्वजारोहण किया।

मुख्य समारोह में आजाद एकेडमी एवं ललित साहू-मोहित साहू ग्रुप ने डांस ड्रामा एवं देश भक्ति गीत प्रस्तुत किए। अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन कम्युनिटी थियेटर के युवा कलाकारों द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जागरुकता नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर इस महामारी से लड़ने के लिए मास्क की उपयोगिता एवं कोरोना वैक्सीनेशन की मेडिकल गाइडलाइन का पालन करने का संदेश दिया। योगा के माध्यम से स्वस्थ शरीर की महत्ता को बताया गया। पुलिस कमाण्डो द्वारा आतंकवादियों द्वारा हाईजेक की गई बस में बैठे यात्रियों को सकुशल मुक्त कराने का सजीव प्रदर्शन किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा झांकी प्रदर्शन में प्रथम स्थान वन विभाग, द्वितीय स्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं तृतीय स्थान जिला परिषद् की झांकी को दिया गया।

चित्तौड़गढ़

72 वां गणतंत्र दिवस इंदिरा गांधी स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः सहकारिता एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री श्री उदयलाल आंजना द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। इसके बाद उन्होंने मार्च पास्ट व परेड की सलामी ली।

सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने श्री गौरक्षक सेवा समिति बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) को वर्ष 2020-21 द्वितीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गौशाला चयनित किये जाने के फलस्वरूप गौपालन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 5 हजार रुपये का चेक, प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न प्रदान किया।

नागौर

जिला स्टेडियम में 72 वें गणतंत्र दिवस का जिलास्तरीय समारोह उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। जिला कलक्टर ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली।

श्रीगंगानगर

गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि जिला कलक्टर ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में राजस्थान सशस्त्र बल की टुकड़ी, राजस्थान पुलिस पुरुष, राजस्थान पुलिस महिला, बॉर्डर होमगार्ड, अर्बन होमगार्ड की टुकड़ियों ने भाग लिया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गए।

शहीद दिवस पर पावन स्मरणांजलि कार्यक्रम

स्कूलों में स्थापित होंगे गांधी-दर्शन कॉर्नर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व एवं उनकी जीवनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने वाली है। आज के इस दौर में गांधीजी के सिद्धांत अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। ऐसे में गांधी दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गांधी दर्शन कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। इससे गांधीजी के विचारों को छात्र-छात्राओं तक पहुंचाने का उचित प्लेटफॉर्म मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 30 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास से शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित पावन स्मरणांजलि कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में नव स्थापित वाइल्ड लाइफ रिसर्च एण्ड कन्जर्वेशन अवेयरनेस सेन्टर एवं गांधी अध्ययन केंद्र के नवीनीकृत कार्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की सोच है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए ताकि हमारे युवा उनके जीवन दर्शन को आत्मसात कर सकें।

गांधी अध्ययन केंद्र गांधी जी के विचारों को युवाओं में प्रसारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। श्री गहलोत ने इस केन्द्र के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रूपये देने की घोषणा की। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में पहले से स्थापित गांधी अध्ययन केन्द्रों को फिर से शुरू किया जाएगा और जहां यह केन्द्र नहीं खुले हैं वहां खोले जाएंगे। उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों में भी गांधी अध्ययन केन्द्र खोलने पर राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। स्कूली पाठ्यक्रम में आजादी के आंदोलन में बापू के योगदान को पर्याप्त स्थान दिया जा रहा है। श्री गहलोत ने युवाओं का आह्वान किया कि वे गांधी जी के विचारों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें।

कार्यक्रम में प्रख्यात गांधीवादी विचारक डॉ. एन. सुब्बा राव ने कहा कि लोगों को आपस में जोड़े रखने में गांधी जी के विचार बहुत प्रासंगिक हैं। सभी देशवासी मिलकर हिंसा मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, भूख मुक्त, नशा मुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त गांधीजी के सपनों का भारत बनाने का प्रण लें। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने गांधी जी द्वारा प्रचारित सात सिद्धांतों का पालन करते हुए न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित जीवन व्यतीत करने तथा मजबूत चरित्र पर जोर दिया। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि गांधी जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए एवं दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। ●

एम. सेंड नीति-2020 का लोकार्पण

राज्य सरकार निर्माण कार्यों के लिए प्रदेशवासियों की बजरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में लाई गई मैन्युफैक्चर्ड सेंड (एम-सेंड) पॉलिसी-2020 गेमचेंजर साबित होगी। इस बहुप्रतीक्षित नीति के कारण प्रदेश में एम-सेंड के उपयोग तथा इसके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। नदियों से निकलने वाली बजरी पर हमारी निर्भरता में कमी आएगी। साथ ही प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले वेस्ट की समस्या का भी समाधान होगा। एम-सेंड इकाइयां लगने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 25 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास पर एम-सेंड नीति-2020 का लोकार्पण किया। पर्यावरण संबंधी प्रक्रिया व न्यायिक आदेशों के बाद प्रदेश में निर्माण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप बजरी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। वर्ष 2019-20 के बजट में बजरी के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में मैन्युफैक्चर्ड सेंड को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एम-सेंड नीति बनाई गई है। प्रदेश की जनता को इस नीति के जरिए एम-सेंड के रूप में प्राकृतिक बजरी का उचित विकल्प उपलब्ध हो सकेगा।

खान विभाग के अधिकारियों द्वारा इस नीति के माध्यम से दी जा रही रियायतों तथा प्रावधानों का उद्यमियों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेशक एम-सेंड निर्माण की इकाइयां लगाने के लिए आगे आएं और पर्यावरण सुरक्षा के साथ-साथ दीर्घकालिक विकल्प के रूप में बजरी की समस्या का समाधान हो सके। निर्माण कार्यों में एम-सेंड प्राकृतिक बजरी का

उपयुक्त विकल्प है। यह विश्वास आमजन में लाने की आवश्यकता को राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रतिपादित किया है।

नीति में एम-सेंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इस नीति में देश के अन्य राज्यों की एम-सेंड नीति का अध्ययन कर प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें संशोधन भी किए जा सकेंगे। प्रदेश में विभिन्न निर्माण कार्यों में करीब 70 मिलियन टन बजरी की मांग है। वर्तमान परिस्थितियों में बजरी की समस्या को दूर करने के लिए यह नीति उपयोगी साबित होगी।

नीति के तहत लगने वाली नई इकाइयां तथा प्रदेश में पहले से ही क्रियाशील एम-सेंड इकाइयां भी देय परिलाभ की पात्र होंगी। निवेशकों के लिए इस नीति में निवेश सब्सिडी, विद्युत शुल्क, भूमि कर तथा स्टांप ड्यूटी आदि के भुगतान से छूट के आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में 20 एम-सेंड इकाइयां क्रियाशील हैं जिनसे प्रतिदिन 20 हजार टन एम-सेंड का उत्पादन हो रहा है। ●

जनजाति परामर्शदात्री परिषद्

जनजाति क्षेत्र विकास के लिए योजनाबद्ध कार्य कर रही है राज्य सरकार

प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता और योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। विगत दो वर्षों में इन क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार से संबंधित विभिन्न घोषणाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया गया है। भविष्य में भी इन क्षेत्रों के विकास को लेकर किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 9 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की बैठक को सम्बोधित किया। आदिवासी क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित कर रही है। जनजाति क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोगों को प्रेरित कर लोगों को पूरा लाभ दिलाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदिवासी क्षेत्रों में वनाधिकार पट्टों से संबंधित प्रकरणों में पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेकर लोगों को राहत पहुंचाएं। उन्होंने वनाधिकार पट्टा वितरण के काम में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सामुदायिक दावों के प्रकरणों पर निर्धारित समय सीमा में निर्णय लिया जाए। श्री गहलोत ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल के लिए घोषित योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाए।

आदिवासी बालक-बालिकाओं को शिक्षा से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना समय की मांग है। यहां के युवाओं को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। राज्य में नव स्वीकृत 9 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के काम को जल्द पूरा करने के प्रयास हो रहे हैं। जनजाति विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सहित अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

श्री गहलोत ने कहा कि इन क्षेत्रों में वन विभाग की आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर विकास परियोजनाओं एवं सड़क निर्माण कार्यों को गति दी जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि राज्य सरकार टीएसपी क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विगत दो वर्षों में यहां के युवाओं को उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सभी टीएसपी छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। साथ ही, बेणेश्वर धाम, समईमाता जैसे धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त श्री जितेन्द्र उपाध्याय ने प्रस्तुतीकरण में बताया कि कोविड के समय 6 लाख जनजाति कृषकों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए संकर मक्का बीज के निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराए गए। जयपुर में 18 करोड़ रूपये की लागत से ट्राइबल यूथ हॉस्टल एवं करियर काउन्सिलिंग सेन्टर तथा प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा में 12 करोड़ रूपये की लागत से इनडोर स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण जल्द पूरा होने वाला है।

बैठक में क्षेत्रीय विधायकों ने जनजाति क्षेत्र के विकास एवं आवश्यकताओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए और कहा कि विगत 2 वर्षों में राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। ●

किशोर स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता

ब्रांड एम्बेस्डर और मैसेन्जर बनाकर संचालित होंगे जागरूकता कार्यक्रम

किशोर स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है। चिकित्सा विभाग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए शिक्षकों को ब्रांड एंबेसडर व छात्रों को मैसेंजर के तौर पर शामिल करेगा। इन कार्यक्रमों में युवावस्था में आने वाली समस्याओं पर खुलकर चर्चा कर उनका निदान भी किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यूएनएफपी के संयुक्त तत्त्वावधान में 3 फरवरी को जयपुर में राज्यस्तरीय शाला स्वास्थ्य व कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के चयनित सात जिलों (बारां, बूंदी, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही, करौली और उदयपुर) के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा, जांच एवं आवश्यक जानकारियां दी जाएंगी। युवा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और राज्य सरकार की तमाम स्वास्थ्य योजनाओं से लाभान्वित हो सकें, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग साथ मिलकर उचित माध्यम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए 'निरोगी राजस्थान' अभियान में भी किशोर स्वास्थ्य को प्रमुख बिंदुओं में शामिल किया गया है। प्रदेश के 42 हजार राजस्व ग्रामों में 80 हजार स्वास्थ्य मित्र बनाए गये हैं। शहरों में भी स्वास्थ्य मित्र के चयन की प्रक्रिया जारी है। स्वास्थ्य मित्रों के जरिए गांव व शहरों में आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य जाएगा, जिससे कि वे स्वस्थ्य व निरोगी रहें।

इस कार्यक्रम के तहत चयनित प्रत्येक स्कूल के 2 शिक्षकों को हेल्थ एंड वैलनेस एम्बेसडर और 2 विद्यार्थियों को संदेशक (मैसेन्जर) के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये शिक्षक प्रति सप्ताह निर्धारित विभिन्न 11 थीम्स (विषय) पर विद्यार्थियों के बीच विस्तृत चर्चा करेंगे और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक करेंगे।

कार्यक्रम के जरिए फरवरी से मई 2021 तक कुल 4 हजार 821 राजकीय विद्यालयों के 9 हजार 642 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा, जो नियमित रूप से सत्रों का संचालन करेंगे। इसके लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें हेल्थ प्रमोशनल गतिविधियों, हेल्थ स्क्रिनिंग एवं आईएफए गोलियों, सेनेटरी नैपकीन से संबंधित विभिन्न सेवाओं को शामिल किया गया है।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कार्यरत स्वास्थ्य दलों, डीईआईसी केन्द्रों, उजाला क्लिनिक एवं आरकेएसके काउंसलर तथा पीआर एजुकेटर्स को सहयोग के लिए इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला एवं ब्लॉक लेवल पर मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन कमेटी बनाई जाएंगी जो स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम गतिविधियों का प्रबंधन करेंगी। ●

पोटाश खनिज के व्यावहारिकता अध्ययन के लिए त्रिपक्षीय एमओयू

तेल एवं गैस के बाद अब पोटाश से मिलेगी राजस्थान को नई पहचान

प्रदेश के नागौर-गंगानगर बेसिन में पोटाश खनिज के व्यावहारिकता अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड तथा भारत सरकार के मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) के बीच 21 जनवरी को त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में हुए इस एमओयू में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी तथा केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल भी जुड़े।

मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री गहलोत ने कहा कि देश को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में राजस्थान का बड़ा योगदान है। राजस्थान खनिजों का खजाना है। हमारा प्रयास है कि इनका समुचित दोहन हो और राजस्थान खनन के क्षेत्र में नंबर वन राज्य बने। इस हेतु एवं पूरे प्रदेश की खनिज संपदा की खोज के लिए कंसलटेंट नियुक्त भी किया जाएगा।

श्री गहलोत ने कहा कि पोटाश के मामले में अभी हमारा देश पूरी तरह आयात पर निर्भर है। हर साल करीब 5 मिलियन टन पोटाश के आयात पर लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर क्षेत्र में फैले पोटाश के भंडारों से हम इस खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। ये एमओयू पोटाश के खनन की दिशा में बढ़ा कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुर्लभ खनिज का मुख्य उपयोग उर्वरक, केमिकल एवं पेट्रो-केमिकल तथा ग्लास सहित अन्य उद्योगों में होता है। प्रदेश में इस खनिज का उत्खनन होने से इन उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व एवं रोजगार में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि मिनरल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एमईसीएल की विशेषज्ञता एवं अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलेगा। राज्य सरकार इसके लिए उन्हें पूरा सहयोग करेगी।

श्री गहलोत ने कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर में तेल एवं गैस की खोज से राजस्थान को नई पहचान मिली है। हमारे प्रयासों से रिफाइनरी की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। आशा है अब हम पोटाश के क्षेत्र में भी देश की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।

केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केन्द्र सरकार माइनिंग सेक्टर में नीतिगत सुधार कर रही है और इस क्षेत्र में कई बाधाओं को दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के लिए जरूरी पोटाश की उपलब्धता के आकलन और खनन की दिशा में हो

रहे इस कार्य में राज्य सरकार से प्रो-एक्टिव सहयोग मिल रहा है।

श्री जोशी ने कहा कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण तथा एमईसीएल ने अपने प्रारंभिक अध्ययन में इस बेसिन में करीब 2500 मिलियन टन खनिज पोटाश की उपलब्धता का आकलन किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार खनन के क्षेत्र में राजस्थान को पूरा सहयोग करेगी।

प्रदेश के खान एवं पेट्रोलियम मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई दशक पहले प्रदेश में पोटाश खनिज के मौजूद होने का आकलन किया था। लेकिन इस दिशा में आगे काम नहीं हो सका। अब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के प्रयासों से इस कार्य को गति मिल सकी है।

केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि पोटाश के खनन से पश्चिमी राजस्थान पोटाश से जुड़े उद्योगों का हब बन सकता है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि इस एमओयू से प्रदेश के अन्य जिलों में खनिज पोटाश की संभावनाओं पर काम हो सकेगा और यह समझौता प्रदेश के खनिज क्षेत्र के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

एमईसीएल के सीएमडी श्री रंजीत रथ ने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि राजस्थान में हर वो खनिज मौजूद है जिसकी देश को जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 700 मीटर गहराई में पोटाश के मौजूद होने का प्रारंभिक तौर पर आकलन किया गया है। राजस्थान के पोटाश भंडारों से देश के विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक इस खनिज की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम श्री अजिताभ शर्मा ने आभार व्यक्त किया। इससे पहले आरएसएमएमएल के एमडी श्री विकास सीताराम भाले, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के निदेशक श्री केबी पांड्या तथा एमईसीएल के सीएमडी श्री रणजीत रथ ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री गोविंद शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ●

हाउसिंग बोर्ड ने बनाया सम्पत्ति विक्रय का रिकॉर्ड

राजस्थान आवासन मण्डल ने 500 सम्पत्तियां बेचकर 135 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। इनमें बुधवार नीलामी उत्सव के तहत 430 सम्पत्तियां बेचकर 42 करोड़ 32 लाख रुपये और 70 प्रीमियम सम्पत्तियों के विक्रय से 92 करोड़ 73 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। राज्य में ई-ऑक्शन के माध्यम से सम्पत्तियों के विक्रय इतना का रिकार्ड बनाया है।

मण्डल द्वारा जयपुर, कोटा, बीकानेर, दौसा और सवाई माधोपुर की प्रतिष्ठित योजनाओं में आवासीय व व्यावसायिक प्रीमियम सम्पत्तियों का ई-अक्शन किया गया, जिसमें लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। इन शहरों में 70 प्रीमियम सम्पत्तियों के विक्रय से मण्डल को 92 करोड़ 73 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि जयपुर की प्रताप नगर योजना में महल रोड पर 2400 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड 15 करोड रुपये में बिका है।

आयुष मार्केट और आतिश मार्केट की 14 दुकानें बिकी 13 करोड़ रुपये में

मण्डल द्वारा जयपुर के प्रताप नगर में विकसित किये जा रहे आयुष मार्केट की 6 दुकानें 2 करोड़ 94 लाख रूपये में बिकी। इसी तरह मानसरोवर योजना में विकसित किये जा रहे आरएचबी आतिश मार्केट में 8 शोरूम भूखण्ड 10 करोड़ 8 लाख रूपये में बिके। रोचक बात यह है कि आतिश मार्केट में भूखण्ड संख्या 66 अपने निर्धारित न्यूनतम बोली मूल्य से 4 गुना कीमत में बिका। इस भूखण्ड का निर्धारित बोली मूल्य 80 हजार रूपये प्रति वर्ग मीटर था जो कि 3 लाख 40 हजार रूपये प्रति वर्ग मीटर में बिका। इसी तरह आयुष मार्केट में 1 भूखण्ड अपने निर्धारित न्यूनतम बोली मूल्य से साढे तीन गुना कीमत में बिका।

जयपुर वृत्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय में 60 सम्पत्तियां बिकी, जिससे मण्डल को 8 करोड़ 2 लाख रूपये का राजस्व मिला। जोधपुर वृत्त प्रथम और द्वितीय में 81 सम्पत्तियां बिकीं, जिससे मण्डल को 7 करोड़ 40 लाख रूपये का राजस्व मिला। कोटा वृत्त में 52 सम्पत्तियां बिकी, जिससे मण्डल को 4 करोड़ 6 लाख रूपये का राजस्व मिला। बीकानेर वृत्त में 120 सम्पत्तियां बिकी, जिससे मण्डल को 10 करोड़ 76 लाख रूपये का राजस्व मिला। उदयपुर वृत्त में 66 सम्पत्तियां बिकी, जिससे मण्डल को 6 करोड 68 लाख रूपये का राजस्व मिला और अलवर वृत्त में 51 सम्पत्तियां बिकी, जिससे मण्डल को 5 करोड़ 40 लाख रूपये का राजस्व मिला। ●

प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद

' मेरे देश की धरती सोना उगले... ' गीत को साकार कर रही है राजस्थान की धरती

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में तेल, गैस के अतिरिक्त पोटाश और सिल्वर जैसे खनिजों के बड़े भण्डार मिलने से हिन्दी सिनेमा के लोकप्रिय गीत 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती...' की कल्पना साकार हुई है। इन खनिजों के उत्पादन से यहां कई प्रकार के नए उद्योग-धंधों के विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को प्रदेश में उपजे इन अवसरों का भरपूर लाभ लेना चाहिए।

श्री गहलोत 23 जनवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम में राजस्थान फाउंडेशन और राजस्थान संघ, तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद कार्यक्रम में उद्‌बोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सहित अनेक एमएसएमई उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए फेसिलिटेशन एक्ट, नई औद्योगिक नीतियां और 'वन स्टॉप शॉप' जैसी सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे उद्यमियों के लिए अधिक सकारात्मक माहौल बना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कई शैक्षणिक एवं औद्योगिक संस्थानों के साथ-साथ आधारभूत विकास के बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इनके चलते आने वाले समय में राजस्थान की सूरत एकदम बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के महत्त्वपूर्ण राजमार्गों के आस-पास औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य गतिविधियां शुरू करने और विभिन्न संभागों में कच्चे माल की उपलब्धता के अनुसार कलस्टर विकसित करने का निर्णय लिया है। साथ ही, प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने के लिए 15 नए औद्योगिक क्षेत्र शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने संवाद कार्यक्रम के दौरान प्राप्त सुझावों पर विचार कर समुचित क्रियान्विति करने का विश्वास दिलाया।

श्री गहलोत ने कहा कि हमारे प्रवासी देश और दुनिया में जहां-जहां भी हैं, हम वहां जाएंगे तथा उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। कोविड-19 महामारी के दौर में दूसरी जगहों पर बसे जिन लोगों को तकलीफें हुई हैं और आने वाले वक्त में उन्हें राजस्थान आने पर क्या-

क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसका पूरा ध्यान राजस्थान फाउंडेशन द्वारा रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर फाउण्डेशन के चैप्टर नहीं हैं, वहां नए चैप्टर खोलकर गतिविधियां शुरू की जाएंगी। साथ ही, जहां पहले से फाउण्डेशन की मौजूदगी है, वहां इसकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को अपने गृह प्रदेश में आकर कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें पूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम उद्यम स्थापना और निवेश से इतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवहार के तहत केरल सहित देश के दूसरे राज्यों अथवा विदेशों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों के साथ संपर्क-संवाद लगातार जारी रखेंगे और हरसंभव मदद करेंगे। इसके लिए प्रदेश में जिला स्तर पर 'नॉन-रेजिडेन्ट राजस्थान सेल' भी स्थापित की जाएंगी। साथ ही, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्रवासियों के लिए विशेष 'ग्रीवेन्स रीड्रेसल विण्डो' के माध्यम से उनकी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।

श्री गहलोत ने कहा कि संवेदनशील और पारदर्शी राजस्थान सरकार ने कोविड महामारी के समय 24X7 काम करके तथा 10-10 घण्टे बैठकें कर प्रदेशवासियों को घातक वायरस के कहर से बचाने के लिए शानदार प्रबंधन किया।

राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव ने संवाद कार्यक्रम में कहा कि कोविड-19 के दौर में मुख्यमंत्री श्री गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने में सफलता के साथ-साथ कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए बेहतरीन प्रबंधन किया जा रहा है।

डब्ल्यूएचओ की रैंकिंग में सभी 5 पैरामीटर को पूरा करने पर राजस्थान को 'मोस्ट एफिशिएंट इंडियन स्टेट फोर कोविड-19 वैक्सीनेशन' घोषित किया गया है। साथ ही, राजस्थान में पहली ड्राइव में केन्द्र सरकार के 90 प्रतिशत वैक्सीन यूटिलाइज के लक्ष्य को प्राप्त कर 97 प्रतिशत वैक्सीन यूटिलाइजेशन करने में सफलता प्राप्त की।

फाउंडेशन आयुक्त श्री श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत की दूरदर्शी सोच से यह मुमकिन हो पाया है कि हम दुनिया के कोने-कोने में बैठे राजस्थानी प्रवासियों को एक साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने दुनियाभर में बसे प्रवासी राजस्थानियों को गृह प्रदेश से जोड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन करवाया था। यह संकल्पना रखी गई थी कि प्रवासियों को राजस्थान में आकर अपनी संस्कृति से जुड़ने तथा राज्य के विकास कार्यों में भागीदार बनने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए स्थाई व्यवस्था बनाई जाए। इसी विचार के साथ मार्च 2001 में राजस्थान फाउंडेशन बनाया गया, जिसका काम देश तथा विदेशों में बसे हुए प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जोड़ने का है। इस अवसर पर सांसद श्री शशि थरूर, अन्य जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में केरल में राजस्थानी प्रवासी और गण्यमान्य उपस्थित थे। ●

अंग प्रत्यारोपण करने वाली चिकित्सकों की टीम को मुख्यमंत्री ने दी बधाई

मृत्यु के बाद भी अंगदाता को गौरवान्वित करता है अंगदान

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर द्वारा एक सप्ताह में दूसरी बार सफलतापूर्वक अंग प्रत्यारोपण करने पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी एवं अंग प्रत्यारोपण करने वाले चिकित्सकों की पूरी टीम को बधाई दी है। श्री गहलोत ने कहा कि देशभर में प्रतिवर्ष हजारों मरीजों की मृत्यु शरीर के महत्त्वपूर्ण अंगों के कार्य करना बंद करने से हो जाती है। ऐसे में सही समय पर अंग प्रत्यारोपित कर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कई मरीजों को जीवनदान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंगदान महादान है। अंगदान कर दूसरों का जीवन बचाना मृत्यु के बाद भी अंगदाता और उसके परिजनों को गौरवान्वित करता है। यह सकारात्मक संदेश आज समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि ब्रेनडेड घोषित किए गए मरीज के परिजन समय पर उस मरीज के अंगों को दान करने के लिए मोटिवेट हो सकें।

सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती 14 वर्षीय विशाल के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद डॉक्टरों की समझाइश से उसके परिजनों ने अंगदान करने का फैसला लिया। इसके बाद विशाल की दो किडनी एसएमएस अस्पताल में ही जरूरतमंदों को लगाई गई। मरीज का लीवर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपुर भेजा गया जबकि दोनों फेफड़े एवं हृदय चार्टर्ड विमान से चेन्नई भेजे गए जहां उनका सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भंडारी ने बताया कि राज्य में कार्यरत स्टेट आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन की टीम डॉ. अमरजीत मेहता, डॉ. मनीष शर्मा, डॉ. अजीत सिंह व रोशन बहादुर तथा सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रांसप्लांट को-ऑर्डिनेटर्स के अथक प्रयासों से विशाल के परिजन को अंगदान के लिए प्रेरित किया गया। ●

दिशा की पहली बैठक

स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर हो मिशन मोड में काम

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं रोजगार से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं समावेशी विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। गांव-ढाणी में बैठे हर जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर इनका लाभ मिले, इसके लिए मिशन मोड में काम करते हुए योजनाओं को गति दी जाए।

3 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की पहली बैठक हुई। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, जल जीवन मिशन, समग्र शिक्षा अभियान तथा नेशनल हैल्थ मिशन से सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आमजन को रोजगार से जोड़ने के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हुई है। कोविड के चुनौतीपूर्ण दौर में इसकी महत्ता और बढ़ी है। राजस्थान इस योजना के क्रियान्वयन में सदैव अग्रणी रहा है। आगे भी इसी भावना के साथ काम किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले बारां की सहरिया एवं खेरवा तथा उदयपुर की कथौड़ी जनजाति के मनरेगा श्रमिकों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बीते दो वर्षों में नियोजित परिवारों की संख्या 50 लाख 65 हजार से बढ़कर 69 लाख 96 हजार हो गई है। साथ ही 99.69 प्रतिशत श्रमिकों को 15 दिवस में भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य प्रीमियम की हिस्सा राशि देकर किसानों के फसल बीमा का भुगतान सुनिश्चित किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना की बाधाओं को दूर करने एवं पारदर्शितापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके लिए अन्य राज्यों में किए गए नवाचारों का अध्ययन किया जाए।

बैठक में बताया गया कि खरीफ-2019 में सभी 17 लाख 55 हजार किसानों के करीब 3153 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया गया है। इसी प्रकार रबी 2019-20 में 920 करोड़ रूपये के क्लेम में से करीब 777 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। रबी 2019-20 में आठ जिलों के काश्तकारों का फसल बीमा भुगतान लम्बित था, जिसमें से 7 जिलों के लिए राज्यांश प्रीमियम जारी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर गांव-ढाणी में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए जल जीवन मिशन योजना को गति दी जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र और राज्य की 50:50 फीसदी की भागीदारी पर संचालित हो रही इस योजना के फंडिंग पैटर्न में बदलाव की आवश्यकता है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि केन्द्र शासित प्रदेशों एवं उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों की तरह राजस्थान की दुर्गम एवं रेगिस्तानी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहां भी यह योजना 90:10 की भागीदारी में संचालित करने के लिए केन्द्र सरकार से फिर अनुरोध किया जाए। बैठक में बताया गया कि मिशन को गति देने के लिए सभी 33 जिलों में जिला स्तरीय तथा 43 हजार गांवों में से 38 हजार गांवों में ग्राम पेयजल स्वच्छता समितियों का गठन कर दिया गया है। शेष गांवों में भी जल्द ही इनका गठन हो जाएगा।

श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के गांव-ढाणी तक मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मॉडल सीएचसी विकसित की जाएं। राज्य की आवश्यकता के अनुरूप जिला अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए योजना तैयार की जाए। स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त चिकित्सा उपकरण एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि लोगों को इलाज के लिए शहरों तक न जाना पड़े। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बेहतरीन क्रियान्वयन से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। साथ ही, वर्ष 2005 में प्रदेश में संस्थागत प्रसव मात्र 32 प्रतिशत होते थे, वे अब बढ़कर 84 प्रतिशत हो गए हैं।

नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री श्री बी.डी. कल्ला, कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचन्द कटारिया, चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, खान मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया, राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती ममता भूपेश, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली, युवा मामलात राज्यमंत्री श्री अशोक चांदना, विधायक श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, श्री जेपी चन्देलिया, श्री राजकुमार गौड़ एवं श्री वाजिब अली ने योजनाओं को लेकर सुझाव दिए।

खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण की सुविधाएं

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दो साल में कई बड़े फैसले लिए हैं। हमारा प्रयास है कि राजस्थान खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान कायम करे। उन्होंने अधिकारियों को खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं लेने के लिए सेवा नियम बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रदेश में करीब 500 बेहतरीन खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जा सकेंगी।

श्री गहलोत 2 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास पर खेल एवं युवा मामलात विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि खेलों को लेकर की गई बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें, ताकि खिलाड़ियों को समय पर इनका समुचित लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास में कोई भी कमी नहीं रखेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की खेल प्रतिभाओं में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उम्दा प्रदर्शन की क्षमता मौजूद है। आवश्यकता है कि उन्हें अच्छा प्रशिक्षण, आवश्यक सुविधाएं और आगे बढ़ने के अवसर मिलें। ऐसे प्रयास करें जिससे गांव और कस्बों तक खेलों के प्रति युवाओं का रूझान बढ़े। उन्हें स्कूल स्तर से ही खेलों की बेहतरीन कोचिंग मिले।

श्री गहलोत ने जयपुर में एसएमएस एवं विद्याधर नगर स्टेडियम तथा जगतपुरा शूटिंग रेंज में विकास कार्यों की आवश्यकताओं, अन्य शहरों और गांव स्तर तक खेल सुविधाओं के विकास के बारे में प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने और निरन्तर नया करने की प्रेरणा देने के लिए वर्चुअल माध्यम से यूथ मॉटिवेशन प्रोग्राम आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

खेल एवं युवा मामलात राज्यमंत्री श्री अशोक चांदना ने कहा कि पिछले वर्ष हुए राज्य खेलों के आयोजन में 8 हजार खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इससे राजस्थान में खेलों के विकास के लिए अच्छा माहौल तैयार हुआ है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए गांव एवं ब्लॉक स्तर पर भी खेलों के आयोजन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पदक विजेताओं को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, आउट ऑफ टर्न नियुक्ति और अन्य खिलाड़ियों को नौकरियों के लिए आरक्षण के नियमों में सरलीकरण से खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है। दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी इन फैसलों की सराहना कर रहे हैं।

शासन सचिव खेल एवं युवा मामलात श्री दिनेश कुमार यादव ने विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने बीते वर्ष गुवाहटी में हुए राष्ट्रीय खेलों में 11वां स्थान हासिल किया। जापान में प्रस्तावित ओलम्पिक एवं पैरालम्पिक खेलों में भी राजस्थान के 9 खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को विभिन्न स्तर पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 26.53 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह

पुलिस अपराधों की रोकथाम करने के साथ ही समाज हितकारी कार्यों में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। कोविड वैश्विक महामारी के दौर में पुलिस ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर स्थापना दिवस को समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने वर्तमान समय के अनुरूप पुलिसिंग रणनीतियों पर जोर देते हुए कहा कि अपराधों के स्वरूप लगातार बदलने तथा नई-नई प्रौद्योगिकी के विकास के कारण पुलिस से पहले की तुलना में उम्मीदें कई गुना बढ़ी हैं। डिजिटल मुद्राओं के चलन के कारण साइबर मनी लॉन्ड्रिंग की नई चुनौती उभर कर सामने आई है। साइबर क्राइम में अपराधियों के बढ़ते रूझान, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के इस्तेमाल और डार्क वेब में ड्रग्स की बिक्री को देखते हुए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित नवीनतम तकनीक से पुलिस को आद्यतन किये जाने की आवश्यकता है, पुलिस विश्वविद्यालय को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

भारतीय संस्कृति से जुड़े जीवन मूल्यों की सीख पुलिस में जाने वालों को कैसे मिले, इसके लिए भी कार्य करने की जरूरत है। पुलिस विश्वविद्यालय को पुलिसिंग, सुरक्षा और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान के साथ ही अकादमिक उत्कृष्टता के लिए कार्य करना चाहिए। पुलिस विश्वविद्यालय संगठित अपराधों की रोकथाम, मानव व्यवहार प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, अपराध मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष पाठ्यक्रम विकसित करे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस सेवा और सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में गहन शोध एवं अनुसंधान के लिए जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर वर्तमान में आ रही चुनौतियों तथा आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने की दिशा में यह विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाए।

दुनिया में तेजी से बदलते हालात, साइबर अपराधों सहित सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पक्षों में मजबूती हासिल करने विश्वविद्यालयों का महत्त्व बढ़ जाता है। राज्य सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के बीच साझेदारी की पेशकश की है। इसके माध्यम से जोधपुर में फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट स्थापित हो सकेगा, जिससे फोरेंसिक विशेषज्ञ तैयार होंगे और पुलिस जांच का कार्य वैज्ञानिक तरीके से हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे महान नेताओं के लंबे संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ और हमें एक मजबूत संविधान मिला। संविधान के सिद्धांतों के कारण ही 70 साल बाद भी हमारे देश में लोकतंत्र कायम रहा। तमाम विभिन्नताओं के बावजूद हमारा देश एक है, अखंड है।

संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों को हर व्यक्ति आत्मसात करे।

मुख्यमंत्री ने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद करने और पुलिस प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। राज्य सरकार ने विगत दो साल में कई नवाचारों के माध्यम से पुलिसिंग को पब्लिक फ्रेंडली बनाते हुए बेहतर कानून-व्यवस्था कायम की है। इन नवाचारों से प्रदेश में अपराधों के निस्तारण में काफी तेजी आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जहां फरियादी को न्याय दिलाने की सोच के साथ अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की गई है। थानों में स्वागत कक्ष बनाए गए हैं। महिला अपराधों की त्वरित तफ्तीश के लिए हर जिले में पुलिस उपाधीक्षक का पद सृजित किया है। इन सबसे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। राज्य सरकार विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने तथा शैक्षणिक उन्नयन के लिए पूरा सहयोग करेगी।

संयुक्त राष्ट्र से संबंधित विषयों के अनुसंधान तथा इस विषय में छात्रों, पेशेवरों और पुलिस अधिकारियों के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन यूएन स्टडीज' की स्थापना की गई है।

'संयुक्त राष्ट्रः 1945 से 2020 एक सिंहावलोकन' पुस्तक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन यूएन स्टडीज के न्यूज लेटर का विश्वविद्यालय ने अध्ययन आरम्भ किया है।

सम्मेलन के दौरान प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार सहित प्रशासनिक, पुलिस एवं विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं शिक्षकगण ऑनलाइन उपस्थित रहे। ●

कैंसर बचाव के प्रयास

अर्ली डिटेक्शन कैंप

कैंसर की जल्दी पहचान ही कैंसर पर नियंत्रण का काम करती है। इसीलिए चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालयों में अर्ली कैंसर डिटेक्शन शिविर लगाए जा रहे हैं। आमजन से शिविरों का लाभ लेने की राज्य सरकार द्वारा अपील की गई है।

विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को आयोजित राज्यस्तरीय संगोष्ठी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि इन शिविरों में एक लाख से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर लगभग 4 हजार संभावित मरीजों को चिह्नित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से होने वाली मौतों में 60 प्रतिशत से अधिक मौतों का मुख्य कारण कैंसर है। दुनिया में 2 करोड़ लोग कैंसर ग्रस्त हैं एवं प्रतिवर्ष 90 लाख नए कैंसर मरीज सामने आ रहे हैं।

भारत में प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या पर 94 पुरुष एवं 104 महिलाएं कैंसर के रोगी हैं। राजस्थान में अनुमानित लगभग 60 हजार व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हैं। कैन्सर का सर्वोत्तम उपचार बचाव ही है। बदलती जीवनशैली, भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ते तनाव, शारीरिक श्रम में कमी के चलते कैंसर जैसी घातक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। जीवन-शैली में सुधार लाकर 60 प्रतिशत मामलों में कैंसर से बचा जा सकता है।

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की प्रभावी रोकथाम के लिये जनचेतना जाग्रत करना आवश्यक है। राज्य सरकार ने प्रदेश को रोगमुक्त करने के लिए 'निरोगी राजस्थान' अभियान की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में ऐसा माहौल बनाना है ताकि लोग बीमार ही न पड़ें। इसके लिए प्रत्येक राजस्व गांव से एक महिला और एक पुरुष को स्वास्थ्य मित्र के रूप में चयन किया गया है।

सरकार सबको स्वास्थ्य का अधिकार देने को कृत-संकल्पित है। कैंसर के जल्दी पहचान कर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिला स्तर पर कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही जिला स्तर पर टेली कॉन्फ्रेंस या टेली मेडिसन के जरिए कैंसर पीड़ितों को परामर्श देने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

आमजन को जागरूक और शिक्षित करके ही बढ़ते कैंसर को नियंत्रित किया जा सकता है। दुनिया में 100 से ज्यादा तरह के कैंसर होते हैं। इनमें मुंह, स्तन और बच्चेदानी का कैंसर प्रमुख है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अर्ली कैंसर डिटेक्शन कैंप लगाकर राहत दी जा रही है। गैर संचारी रोगों में कैंसर मुख्य बीमारी है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ●

किसानों की खुशहाली का है पूरा ध्यान : मुख्यमंत्री

कृषि, पशुपालन एवं इससे जुड़े क्षेत्रों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं पानी की कमी के बावजूद किसानों ने अपनी मेहनत से कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी पायदान पर रखने का सार्थक प्रयास किया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि बजट में ऐसे प्रावधान करें, जिससे राज्य के किसानों तथा पशुपालकों की आय बढ़े और वे खुशहाल हों।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 6 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ के पदाधिकारियों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कृषि और डेयरी विकास की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। तकनीक और नवाचारों के माध्यम से इन क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सकता है। प्रगतिशील किसान और पशुपालकों के सुझाव इसमें महत्त्वपूर्ण होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान और पशुपालकों का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसके लिए हमने विगत दो सालों में कई अहम फैसले लिए हैं, जो कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 55 लाख किसानों को लगभग 8 हजार करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। वर्ष 2020-21 में एक करोड़ 8 लाख किसानों का फसल बीमा किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 24 लाख अधिक है।

कृषि उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 'राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019' लागू की है। यह नीति किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। किसान इस नीति का लाभ लेकर कृषि उद्योगों एवं निर्यात की तरफ कदम बढ़ाएं। राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। हमारी सरकार ने किसानों को खाद एवं बीज की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही टिड्डी की समस्या का भी सफलतापूर्वक सामना किया। कृषि विभाग एवं टिड्डी चेतावनी संगठन ने किसानों के साथ मिलकर 5 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण किया। कोविड-19 के कठिन दौर में आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को मक्का और बाजरा के बीज का नि:शुल्क वितरण किया गया। साथ ही, किसानों को कृषि उपकरणों की नि:शुल्क सेवा उपलब्ध कराई गई। हमारी सरकार ने न केवल प्रदेशवासियों के लिए नि:शुल्क दवा और जांच की व्यवस्था की, बल्कि मूक पशुओं के लिए भी 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क पशुधन दवा योजना' लागू की। योजना में दवाओं की संख्या भी बढ़ाई गई है।

प्रदेश में पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए राज्य सरकार बूंद-बूंद और फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दे रही है। किसान इन पद्धतियों का अधिकाधिक उपयोग कर अपना उत्पादन बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने खेतों में सोलर पैनल लगाकर किसानों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना लागू की थी। हम योजना को और आगे बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में देशभर में चल रहा किसानों का आंदोलन चिंता का विषय है। हमारी सरकार ने उनके हितों का संरक्षण करने के लिए राज्य विधानसभा में तीन कृषि बिल पारित किए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को किसानों की पीड़ा समझकर उनका मान-सम्मान रखते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कहा कि किसानों ने अपने अथक परिश्रम से हमेशा ही प्रदेश का मान-सम्मान बढ़ाया है। कोविड के चुनौतीपूर्ण दौर में भी उन्होंने राज्य सरकार का पूरा सहयोग किया। हमारी सरकार उनकी तरक्की में किसी तरह की कमी नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा और प्रगतिशील किसान नवीन तकनीकों और नवाचारों को अपनाकर कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा दें।

प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं पशुपालन श्री कुंजीलाल मीणा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोविड के दौर में भी किसानों को राहत देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की। इस वर्ष एमएसपी पर गेहूं की 22 लाख मैट्रिक टन खरीद की गई, जो विगत वर्ष की तुलना में 8 लाख मैट्रिक टन अधिक है। उन्होंने कहा कि बैठक में प्राप्त उपयोगी सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में प्रतिभागियों ने किसानों और पशुपालकों के कल्याण की दिशा में विगत दो वर्षों में लिए गए फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णयों से किसानों और पशुपालकों को बड़ा सम्बल मिला है। उन्होंने कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा किए गए बेहतरीन प्रबंधन की भी सराहना की।

इस दौरान शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री गोविंद शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, शासन सचिव पशुपालन डॉ. आरूषि ए. मलिक, आयुक्त कृषि डॉ. ओमप्रकाश, निदेशक कृषि विपणन श्री ताराचंद मीणा सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे। ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला, गोपालन मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया, जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया, सहकारिता राज्यमंत्री श्री टीकाराम जूली एवं कृषि राज्यमंत्री श्री भजन लाल जाटव वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े। ●

मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता प्रदान करने के नियमों में शिथिलता प्रदान कर जोधपुर जिले के गंभीर बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन प्रकरणों में निर्धारित राशि से अधिक राशि स्वीकृत करने की मंजूरी भी प्रदान की है।

कमला नेहरू नगर निवासी सुरेन्द्र आचार्य का गुर्दा प्रत्यारोपण होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता की मांग की जिस पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष नियमों में शिथिलता प्रदान कर 5 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की। जिसे प्रार्थी के खाते में हस्तांतरित भी किया जा चुका है। इसी प्रकार माता का थान निवासी श्रीमती भगवती के परिवार के तीन सदस्यों के दिव्यांग होने के कारण सहायता की मांग की। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के जीवन को सार्थक व सामर्थ्यवान बनाने की दिशा में विभिन्न बड़े कदम उठाए है ऐसे में एक ही परिवार के तीनों सदस्यों के दिव्यांग होने पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए केलीपर, पावर व्हील चेयर, एवं ऐक्टिव व्हील चेयर के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख 40 हजार रूपए की सहायता स्वीकृत की जिसे प्रार्थी के खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है।

इसी प्रकार जोधपुर निवासी पारसराम जी लीवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। परिजनों ने उनका लीवर प्रत्यारोपण करवाया। जिस पर करीब 10 लाख रुपए का व्यय हुआ। उपचार के बावजूद पारसराम की मृत्यु हो गई। आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहे परिवार ने जब मदद के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष गुहार लगाई तो मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष के नियमों में शिथिलता की स्वीकृति प्रदान की और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के उपरांत पीड़ित परिवार को तत्काल प्रभाव से राशि स्वीकृत कर राहत पहुंचाई गई। ●

साक्षी पुरोहित

'हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी'

पुस्तक का विमोचन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की ओर से 'स्वतंत्रता के अमर पुरोधा' शृंखला के तहत प्रकाशित पहली पुस्तक 'हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी' का विमोचन किया।

श्री गहलोत ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए अकादमी का यह प्रयास स्वागत योग्य है। इससे युवाओं को देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान स्वाधीनता सेनानियों के जीवन संघर्ष से परिचित होने का अवसर मिलेगा।

युवाओं और महिला प्रोफेशनल्स की प्रगतिशील सोच से

विकास को मिलेगी नई दिशा : मुख्यमंत्री

युवा, महिला शक्ति एवं प्रतिभावान विद्यार्थी इस देश का भविष्य हैं। उनकी ऊर्जा और क्षमताओं से देश और प्रदेश के विकास को नई सोच के साथ नई दिशा दी जा सके, इसके लिए राज्य सरकार लगातार फैसले ले रही है। आने वाले बजट में भी इन वर्गों के लिए समुचित प्रावधान कर विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से युवा, महिला प्रोफेशनल्स एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिला उद्यमिता को बढ़ावा देकर महिला सशक्तीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, युवा उद्यमियों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी नीतिगत फैसलों और योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए एक हजार करोड़ रूपये की लागत से इन्दिरा महिला शक्ति योजना प्रारम्भ की है। साथ ही, महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित विषयों पर शोध के लिए हरिशचन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान में इन्दिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान की स्थापना की गई है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आसान शर्तों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। जनजाति बाहुल्य जिलों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लागू की गई है। राज्य के महिला थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।

महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार और विकास में भागीदार बनाने के लिए दहेज, घूंघट एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन बेहद जरूरी है। समाज की प्रबुद्ध एवं प्रोफेशनल महिलाएं एवं युवा वर्ग इन बुराइयों को दूर करने के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें। उनकी प्रगतिशील सोच से ही समाज और प्रदेश आगे बढ़ेगा।

शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने जिन पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी हैं, वे प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवाओं को प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को और प्रभावी बनाने तथा रोजगार कार्यालयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर बल दिया।

खेल एवं युवा मामलात राज्यमंत्री श्री अशोक चांदना ने कहा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में पहली बार राज्य खेलों का सफल आयोजन किया। पदक विजेताओं को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, आउट ऑफ टर्न नियुक्ति और अन्य खिलाड़ियों को नौकरियों के लिए आरक्षण के नियमों में सरलीकरण से राज्य में खेलों के प्रति युवाओं का रूझान बढ़ा है। इन प्रयासों से हम आने वाले वर्षों में राज्य को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में कामयाब हो सकेंगे। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने

आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों के हित में अभूतपूर्व कदम उठा रही है। आने वाले समय में भी इन वर्गों को प्रोत्साहित करने में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में प्रदेश के युवाओं और महिलाओं ने आगे बढ़कर सरकार का सहयोग किया। विद्यार्थियों ने भी जनजागरूकता अभियान में अहम योगदान दिया।

खिलाड़ियों ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा हुआ है और वे आजीविका की चिंता से मुक्त होकर खेल मैदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिला प्रोफेशनल्स, प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं ने आगामी राज्य बजट 2021-22 को लेकर महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।

शासन सचिव महिला एवं बाल विकास श्री के.के. पाठक ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने युवा, महिला प्रोफेशनल्स एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए विगत दो वर्षों में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बैठक के प्रतिभागियों से प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। ●

स्वयंसेवी संगठनों एवं सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद

प्रदेश के समन्वित विकास में सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के समन्वित विकास के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। बजट तैयार करने में सभी के सुझावों को शामिल करने के साथ राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के लिए बजट में समुचित प्रावधान कर प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेगी।

श्री गहलोत ने 6 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आए संकट के दौरान स्वयंसेवी संगठनों ने जरूरतमंदों की मदद करने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग किया। 'कोई भूखा नहीं सोये' के हमारे संकल्प को पूरा करने में विभिन्न संगठनों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। इसके लिए सभी को साधुवाद।

सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यों में राज्य सरकार ने हमेशा प्रगतिशील सोच के साथ फैसले लिये हैं। प्रदेश में गरीबों एवं वंचित वर्गों को केन्द्र में रखकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कई कदम उठाए गए। वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कुल 37 करोड़ 19 लाख मानव दिवस सृजित कर प्रदेश के 70 लाख 93 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। नरेगा श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् द्वारा जनवरी 2021 तक 1 लाख 84 हजार 994 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 21 लाख 50 हजार ग्रामीण महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया। साथ ही, 13 हजार 465 ग्राम संगठनों एवं 482 क्लस्टर लेवल फेडरेशनों का गठन कर परियोजना में अब तक 1805 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रदेश में वर्ष 2020-21 में 13 लाख 33 हजार 394 आवास की स्वीकृति जारी की गई और करीब 10 लाख 10 हजार से अधिक आवासों का निर्माण किया जा चुका है। शेष के कार्य प्रगति पर है।

राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही उनके प्रभावी क्रियान्वयन में नागरिक संगठनों एवं एनजीओ की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नवाचार अथवा नई योजना की आवश्यकता के संबंध में दिए गए मूल्यवान एवं सारगर्भित सुझावों को आगामी बजट में स्थान देने की आवश्यकता है। स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कोरोना के बेहतरीन प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की खुलकर तारीफ की और कहा कि राजस्थान सरकार के प्रबंधन की देश-विदेश में सराहना हुई है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज श्री रोहित कुमार सिंह ने बैठक की शुरुआत में सभी का स्वागत किया और कहा कि प्रतिभागियों से प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। ●

राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक

अर्थव्यवस्था को नई गति देगा प्रदेश का बजट : मुख्यमंत्री

राज्य सरकार का प्रयास है कि राज्य का बजट विकास को गति देने वाला एवं संतुलित बजट हो। कोविड-19 महामारी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं राजस्व पर बुरा असर डाला है। इससे तेजी से उबरने की इच्छाशक्ति के साथ हम सभी के सुझावों के आधार पर समावेशी बजट लाने का प्रयास करेंगे, जिससे राज्य में उद्योगों और निवेश को प्रोत्साहन मिले, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो तथा समाज के हर वर्ग की उन्नति हो।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यस्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से राज्य बजट 2021-22 के लिए सुझाव जाने।

राजस्व पर विपरीत असर के बावजूद हर वर्ग को दी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से चली लंबी जंग के कारण देश के सभी राज्यों की राजस्व आय प्रभावित हुई है। राजस्थान भी इसके असर से जूझ रहा है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने बजट में पेट्रोल एवं डीजल पर सैस लगाया है और बेसिक एक्साइज डयूटी को लगातार कम किया जा रहा है, लेकिन स्पेशल एक्साइज डयूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। इसके कारण डिविजिएबल पूल के रूप में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा काफी घट गया है। अधिकतर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में भी राज्य का हिस्सा बढ़ाते हुए केन्द्र के अंश को कम किया गया है। इन सबका प्रतिकूल असर राज्यों के राजस्व पर हो रहा है। इन तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल पर 2 प्रतिशत वैट कम कर आमजन को महंगाई की मार से राहत दी है। इतना ही नहीं कोरोना काल के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पर्यटन एवं होटल उद्योग तथा बस ऑपरेटर्स सहित अन्य वर्गों को राहत देने में कोई कमी नहीं छोड़ी।

बेहतर वित्तीय प्रबंधन से करेंगे चुनौती का सामना

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के कोरोना प्रबंधन की सराहना पूरे देश में हुई है। पिछले करीब एक साल से सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, सोशल एक्टिविस्टों, व्यापारिक संगठनों सहित तमाम प्रदेशवासियों से हमें भरपूर सहयोग एवं समर्थन मिला है। आगे भी इसी भावना के साथ सभी के सहयोग से मुश्किल आर्थिक हालातों का सामना बेहतर वित्तीय प्रबंधन से करेंगे। पूरा देश कोरोना के कारण आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहा है, ऐसे में उद्योग जगत की बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हर पहलू पर काम कर रही है।

ऊर्जा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि कोरोना की विपरीत

परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के उद्यमियों ने उत्पादन बढ़ाने में पूरा सहयोग किया है। राज्य सरकार उद्यमियों की बिजली से संबंधित समस्याओं का सकारात्मक रूप से समाधान करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरों में एक रूपये प्रति यूनिट की कमी की गई है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्यमियों के वाजिब सुझावों पर अमल करने का प्रयास किया जाएगा।

उद्योग मंत्री श्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप शॉप, रिप्स-2019, नई औद्योगिक नीति, एमएसएमई एक्ट जैसे कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले किए हैं। इनसे प्रदेश में निवेश का वातावरण बनने के साथ ही उद्यमों की स्थापना में आसानी हुई है। उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार उपखण्ड स्तर तक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रयास कर रही है।

प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा ने बजट को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपयोगी सुझावों को राज्य बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

इस अवसर पर सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फोर्टी, पर्यटन, खाद्य पदार्थ व्यापार, एग्रीकल्चर इण्डस्ट्री, ऑयल इण्डस्ट्री, हैण्डीक्राफ्ट, कपड़ा उद्योग, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, मार्बल एवं स्टील उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं व्यापार तथा उद्योग से जुड़े विशेष आमंत्रित सदस्यों ने आगामी राज्य बजट को लेकर सुझाव दिए।

सभी ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कोरोना प्रबंधन तथा उद्योगों के प्रति सकारात्मक रवैये की सराहना की। ●

मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश जारी

आठ जिलों के किसानों को जल्द मिलेगी राहत

रबी 2019-20 में फसल खराबे का मुआवजा

राज्य के चूरू सहित आठ जिलों के किसानों को रबी 2019-20 में हुए फसल खराबे का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा जल्द मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। श्री गहलोत ने 4 फरवरी को राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन आठ जिलों का रबी 2019-20 का क्लेम भुगतान बकाया है, उनका शीघ्र भुगतान किया जाए।

उल्लेखनीय है कि कोरोना लॉकडाउन अवधि में कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा चूरू जिले में किए गए फसल खराबे के प्रयोगों (आकलन) पर बीमा कम्पनी ने असहमति व्यक्त करते हुए भारत सरकार के समक्ष अपील कर दी थी। इसके चलते किसानों के क्लेम का भुगतान नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार ने इस मामले में मजबूती से पैरवी करते हुए किसानों का पक्ष रखा। भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर बीमा कम्पनी की अपील को 3 फरवरी को खारिज कर दिया। अब चूरू जिले की 1 लाख 30 हजार बीमा पॉलिसियों के विरूद्ध पात्र किसानों को 550 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान मिल सकेगा।

इसी के साथ राज्य सरकार ने अजमेर, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा, पाली एवं सवाईमाधोपुर जिलों के रबी 2019-20 के राज्यांश प्रीमियम की 70 करोड़ रूपये की राशि भी बीमा कम्पनियों को जमा करा दी है। इन जिलों के किसानों का बकाया बीमा क्लेम का भुगतान भी जल्द हो सकेगा। ●

शहादत पर नमन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना के जवान जोधपुर जिले की तहसील बिलाड़ा के खेजरला गांव के निवासी श्री लक्ष्मण की शहादत पर नमन किया है।

पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के दौरान शहीद हुए जवान की शहादत को नमन करते हुए कहा कि लक्ष्मण ने मातृभूमि के लिए बलिदान देकर देश और प्रदेशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

राष्ट्रीय महिला दिवस

समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने की आवश्यकता

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा है कि समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की जरूरत है। प्रदेश की तरक्की में महिलाओं ने सशक्त भागीदारी निभाई। देश की आजादी में महिलाओं ने पुरूषों के बराबर भूमिका निभाई तथा पूर्व राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू जैसी अनेक महिलाओं ने आजादी के आन्दोलन में भाग लिया।

श्रीमती सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाये जाने वाले राष्ट्रीय महिला दिवस (13 फरवरी) के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में महिला एवं बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा की रोकथाम रणनीति के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी को नमन् करते हुए आह्वान किया गया कि समाज में रूढ़ीवादी भावना को खत्म करने के लिए सभी को संकल्प लेने की आवश्यकता है।

राजस्थान की तरक्की में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकार द्वारा बेटी बचाओं व बेटी पढ़ाओं के संदेश को आगे बढ़ाते हुए समाज में जन जागरण का वातावरण तैयार करने का अभियान भी चला रखा है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप राज्य में ''इन्दिरा महिला शक्ति निधि'' के तहत प्रदेश की बालिकाओं व महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जा रहे है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। महिलाएं पहले की तुलना में अब ज्यादा जागरूक हुई हैं। इसके लिए अनेक महिला संगठनों व स्वंयसेवी संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। सभी संगठन महिला सुरक्षा रणनीति तैयार करने और समाज में भयमुक्त वातावरण बनाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान व सुझाव प्रदान कर राजस्थान की तरक्की के लिए कार्य करें।

महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव डॉ. के. के. पाठक ने कहा कि राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं का सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग द्वारा अनेक योजना व कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने एवं पीड़ित महिला की सुनवाई तथा सहायता के लिए वन स्टॉप सखी केन्द्र व महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, महिला हेल्पलाईन एवं राज्य महिला आयोग द्वारा कार्यरत वन स्टॉप सेन्टर में किसी भी अपराध एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को त्वरित राहत प्रदान की जाती है। इसके तहत महिलाओं व बालिकाओं को परामर्श, पुलिस एवं चिकित्सा सुविधा तथा आवश्यकतानुसार आश्रय व्यवस्था भी प्रदान की जाती है। ●

उत्पादों की बिक्री के लिए बनेगा ऑनलाइन पोर्टल

स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन से महिला सशक्तीकरण

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश की लोक कल्याणकारी सरकार ने हर वर्ग के कल्याण की प्रतिबद्धता के साथ ही आधी आबादी को भी विकास क्रम में शीर्ष प्राथमिकता पर रखा है। महिलाओं के आर्थिक संबलन हेतु ग्राम्य व शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें संबल प्रदान करने की दिशा में अभिनव पहल की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री गहलोत की जनकल्याण की मंशा के अनुरूप महिला सशक्तीकरण की दिशा में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका), महिला एवं बाल विकास और स्वायत्त शासन विभाग महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु नये कदम उठाये जा रहे हैं। इसी शृंखला में ग्रामीण एवं शहरी स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों की सहज उपलब्धता, गुणवत्ता, ब्रांडिंग व प्रतिस्पर्धात्मक विपणन हेतु पंचायतीराज के तहत महिला एवं बाल विकास, स्वायत्त शासन विभाग तथा राजीविका मिल कर समन्वित प्रयास करेंगे। इन तीनो विभागों के स्वयं सहायता समूह अब राजीविका के बैनर तले एक ब्रांड बनाकर बाजार में उतारेंगे।

इन प्रयासों को अमलीजामा पहनाने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास श्री कृष्ण कान्त पाठक, स्वायत्त शासन सचिव, श्री भवानी सिंह देथा व स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका श्रीमती शुचि त्यागी सहित महिला सशक्तीकरण प्रोजेक्ट्स से जुड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सिंह ने स्वयं सहायता समूहों की समस्त गतिविधियों के लिये व बाजार में पैठ मजबूत बनाने के लिये कॉमन ऑनलाइन पोर्टल बनाये जाने वाले बिन्दुओं जैसे स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु ऑनलाइन आवेदन, विशिष्ट योजनायें, प्रशिक्षण, वित्त, मार्केटिगं, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग, फेसिलिटेटर्स, नवाचार, प्रारूप, उत्पाद, परिवेदनायें व हैल्पलाइन आदि पर विस्तृत चर्चा की।

श्री पाठक ने बताया कि आन्ध्रप्रदेश, सहित देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान राज्य में भी महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में उल्लेखनीय काम हुआ है । महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों के सम्मुख अपने कारोबार का रिकार्ड संधारण बड़ी समस्या रहा है। केवल एक ही रजिस्टर से उन्हें सभी गतिविधियों की जानकारी मिल सके तथा वे स्वयं अपडेट रह सकें इस हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने पर सहमति बनी है। इस पोर्टल से राज्य के सभी महिला स्वयं सहायता समूह जुड़ सकेगें व एक ही जगह पर समस्त गतिविधियों का विस्तार कर सकेंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने कहा कि राजीविका के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह के अधिकतर कार्य कृषि से जुड़े हुए हैं। उनका प्रयास है कि ये स्वयं सहायता समूह आजीविका में पर्याप्त बढ़ोतरी के लिए गैर कृषि क्षेत्र (नॉन फार्म सैक्टर) से भी जुड़ें ताकि वैल्यू एडिशन बढ़ सके। स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद उच्च गुणवत्ता के हैं एवं ब्रांडेड कम्पनियों के उत्पादों की तुलना में सस्ते भी हैं, मगर पैंकिगं, पैकेजिंग व मार्केटिंग की गुणवत्ता के अभाव में इन उत्पादों का विक्रय कम हो पा रहा है। इसके समाधान के लिये ही तीनों विभागों ने सामंजस्य स्थापित कर एनयूएलएम के तहत संचालित स्वयं सहायता समूहों को अब राजीविका की एक ही छत के नीचे लाया जा रहा है। इस हेतु तीनों विभागों के अधिकारी साथ मिल कर समन्वित प्रयास करने हेतु सहमत हो गये हैं। इस संबध में एक प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा गया है।

इस नवाचार से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा में टिक सकेगें व बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ा सकेगें। इसके साथ-साथ इन सम्मिलित प्रयासों से महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच विभिन्न नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संचालित स्वंय सहायता समूहों का भेद भी मिटेगा। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राजीविका के तहत उठाये गये इस बीड़े से ग्रामीण परिवेश में इन स्वयं सहायता समूहों के तहत कार्यरत महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बन कर अपने परिवारों को संबल प्रदान कर सकेंगी। ●

मोती लाल वर्मा

राज्य सरकार का ध्येय

तकनीकी शिक्षा के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना

राज्य सरकार का ध्यान रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा पर केन्द्रित है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसको दृष्टिगत रखकर तकनीकी शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के साथ-साथ पॉलीटेक्निक शिक्षा के पाठ्यक्रम को सेमेस्टर आधारित एवं अद्यतन किया है। तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों का विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट कराये जाने के लिए सेन्टर फॉर ई-गवर्नेस (सी.ई.जी.) को सेन्ट्रल प्लेसमेंट एजेन्सी बनाया गया है।

च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को सभी पाठ्यक्रमों में लागू किया गया है। प्रदेश में पॉलीटेक्निक/अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों के लिए नई उच्च अध्ययन नीति लागू की गई है। **तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) तथा सूचना एवं जनसम्पर्क राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग का तकनीकी शिक्षा पर दृष्टिकोण।**

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी गजाधर भरत के द्वारा किये गए साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश।

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का स्वरूप क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तकनीकी शिक्षा के लिए क्या चुनौतियां हैं?

वर्तमान में तकनीकी शिक्षा के दो विश्वविद्यालय हैं। सोसायटी मोड में 11 स्वायत्तशाषी अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं। निजी क्षेत्र में 72 अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं। इसी प्रकार प्रदेश में 44 राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय हैं और निजी क्षेत्र में 86 पॉलीटेक्निक महाविद्यालय हैं। तकनीकी शिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत महाविद्यालयों के माध्यम से स्नातकोत्तर, स्नातक तथा डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तकनीकी शिक्षा को रोजागारोन्मुखी बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार का ध्यान रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा पर केन्द्रित है।

वर्तमान समय की जरूरत को ध्यान में रखकर तकनीकी शिक्षा में कौनसे परिवर्तन किये हैं?

युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो इसको दृष्टिगत रखकर तकनीकी शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के साथ-साथ पॉलीटेक्निक शिक्षा के पाठ्यक्रम को सेमेस्टर आधारित एवं अद्यतन किया है।

च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को सभी पाठ्यक्रमों में लागू किया गया है। आरटीयू कोटा द्वारा बी-टेक, एम-टेक, एमबीए एवं एमसीए के पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है। एमसीए के पाठ्यक्रम की अवधि को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 3 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष किया गया है। तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षण किया जा सके इस हेतु प्रदेश में पॉलीटेक्निक/अभियांत्रिकी महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए सरलीकृत नवीन उच्च अध्ययन नीति लागू की गई है।

औद्योगिक मांग के अनुसार पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में नवीन शाखाएं खोली गई हैं। सत्र 2020-21 से 19 पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में विद्यमान ब्रांच की क्षमता में परिवर्तन करते हुये व्यवसाय उन्मुखी नवीन ब्रांच यथा रोबोटिक्स, मैकेट्रोनिक्स, साइबर फोरेंसिक इन्फोरमेशन, विजुअल ग्राफिक्स, फैशन डिजाइनिंग, फैशन एण्ड टेक्सटाइल डिजाइन तथा चार अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एंड डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अल्प अवधि कोर्स यथा ऑटोकेड, रेफ्रिजरेशन अनुरक्षण विषय के कोर्स प्रारंभ किए गए हैं।

विद्यार्थियों का प्लेसमेंट कैसे हो? इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने क्या उपाय किए हैं?

तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों का विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट कराये जाने के लिए सेन्टर फॉर ई-गवर्नेस (सी.ई.जी.) को सेन्ट्रल प्लेसमेंट एजेन्सी बनाया गया है। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे कोर्सेज प्रारम्भ किये जा रहे हैं, जो युवा वर्ग को कॉर्पोरेट संस्थानों में अधिक से अधिक नौकरी के अवसर उपलब्ध करवा सके। तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से इस हेतु कॉर्पोरेट संस्थानों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को करियर निर्माण के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सीआईआई के प्रतिनिधियों तथा

एआईसीटीई के अध्यक्ष के साथ बैठकें भी आयोजित की गई हैं। समस्त पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में आई.आई.आई- (Industry Institute Interaction) सेल में स्टूडेंट एडवाइजरी एवं गाइडेंस ब्यूरो चालू कर दिये गये हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पॉलीटेक्निक एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में संचालित ट्रेनिंग एवं प्लेसमेन्ट सेल की ओर से उद्योगों से वर्ष 2015-16 से 2018-19 चार वर्षों में कुल 9 एमओयू हुए जबकि वर्ष 2019-20 में एक वर्ष में ही 23 एमओयू विभिन्न उद्योगों के साथ सम्पादित किये गये हैं। आरटीयू कोटा द्वारा एआईसीटीई, सीबीआरआई, ईसीआई, सीडीएसएस और आईआईटी बीएचयू सहित कई राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से 22 एम.ओ.यू. किये गये हैं।

टेक्यूप का क्या उद्देश्य है?

टेक्यूप योजना तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन के लिए संचालित की जा रही है। TEQIP-III परियोजना के अन्तर्गत कक्षाओं को डिजिटल बोर्ड, एलसीडी प्रोजेक्टर इत्यादि से भी सुसज्जित किया जा रहा है। महाविद्यालयों में सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग व एफडीपी संचालित किये जा रहे हैं। TEQIP-III परियोजना में अप्रेल, 2017 से सितम्बर, 2020 तक के लिए एनपीआईयू द्वारा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों को 130 करोड़ रूपये आवंटित किये गए थे। अप्रेल, 2017 से दिसम्बर, 2018 तक मात्र 17 करोड़ 57 लाख का उपयोग किया गया। जनवरी, 2019 से अब तक 67 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की बैठकें आयोजित कर लगभग 91 करोड़ रूपये का उपयोग कर लिया है। साथ ही 15 करोड़ की राशि के उपयोग की कार्यवाही अपने अंतिम चरण में है। टेक्यूप में अधिकतम फंड का उपयोग किया जा रहा है।

तकनीकी शिक्षा में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की घोषणा की पालना में बांसवाड़ा में डिजिटल लाईब्रेरी विकसित की जा रही है। पूरे सिस्टम में नेटवर्किंग स्थापित करते हुये ब्रॉडकास्टिंग फैसलिटिज हेतु स्टूडियो का निर्माण किये जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा में निरन्तर नवाचार किये जा रहे हैं। कोरोना काल में ऑनलाईन अध्ययन का वातावरण रहा। स्टूडियो के माध्यम से ई-लैक्चर्स तैयार कर हम ऑनलाइन एजुकेशन का अधिकतम उपयोग करना सुनिश्चित करने हेतु कार्य कर रहे हैं। विभाग के तकनीकी उपकरणों का बेहतर उपयोग करने के लिए तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों के अलावा अन्य विद्यार्थियों के लिए 3 और 6 महिनों के सर्टिफिकेट कोर्स करवाने की कार्य योजना है।

विद्यार्थियों को ऑनलाईन ई-कन्टेन्ट उपलब्ध करवाया जाना समय की आवश्यकता है। एप बनाकर सभी विषयों के पाठ्यकम को ई-कन्टेन्ट में परिवर्तित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए एप में उत्तरोत्तर अपडेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ पाठ्यक्रम से सम्बन्धित समस्त सामग्री यथा ई-लेक्चर्स, लैब मैन्यूल, प्राविधिक शिक्षा मण्डल की पूर्ण परीक्षाओं के पेपर बहु विकल्पी प्रश्न, ई-नोट्स नि:शुल्क उपलब्ध करवाने पर कार्य भी किया जा रहा है। इस तरह के नवाचार तकनीकी शिक्षा में नये आयाम स्थापित करेंगे। तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय कोटा परिसर में 2 करोड़ रूपये की लागत से 12 हजार 217 वर्गमीटर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन 3 स्टार ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है। आर.टी.यू. परिसर में विश्व स्तरीय कैफेटेरिया एवं लाइब्रेरी का निर्माण भी शीघ्र करवाये जाने की योजना है।

संस्कृत शिक्षा के लिए आपका क्या विजन है?

संस्कृत शिक्षा का प्रदेश में सुदृढ़ीकरण करना राज्य सरकार का उद्देश्य है। संस्कृत शिक्षा में तकनीक के प्रयोग से नवाचार करना एवं इसे नवीन परिप्रेक्ष्य में लाना ही प्रदेश की वर्तमान सरकार का विजन है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम निरन्तर प्रयासरत हैं। हमने संस्कृत शिक्षा के कार्य सुविधाजनक एवं त्वरित गति से सम्पादित किए जाने के लिए शालादर्पण पोर्टल शुरु किया। पोर्टल में संस्कृत शिक्षा की सूचनाओं का ऑनलाइन अपडेशन उपलब्ध है।

संस्कृत शिक्षा में भर्तियों की प्रक्रिया शुरु की गई है वहीं लम्बे समय से प्रतीक्षित पदोन्नतियां भी दी गई हैं। संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 'देववाणी मोबाइल एप' शुरु किया गया है। इस एप का उद्देश्य संस्कृत शिक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थियों को ई-लर्निंग व एम-लर्निंग के अवसर मुहैया कराना है।

कोरोना काल में सरकार का मुख, आंख, कान कहे जाने वाले सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की क्या चुनौतियां रहीं?

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में मीडिया तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा लिये गये जनकल्याणकारी निर्णयों को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने जन-जन तक पहुंचाया है। कोरोनाकाल में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं मीडिया कर्मियों का आगे रहकर समाज में काम करना चुनौतीपूर्ण रहा है। मुझे खुशी है कि चुनौतियों के बाद भी यह विभाग लक्ष्यों पर खरा उतरा है। सूचना एवं जनसम्पर्क के विभाग ने समूचे मीडिया तंत्र के सहयोग से राज्य सरकार के 'कोई भी भूखा न सोए' के ध्येय को तथा 'मास्क ही वैक्सीन है' के मंत्र एवं कोरोना से बचाव के कुशल प्रबंधन को जन-जन तक पहुंचाया।

चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच

समयबद्ध पेयजल प्रबंधन बना जनसेवा की नई मिसाल

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व एवं जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी कल्ला के सजग प्रयासों से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने राज्य सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गांव-ढाणी, कस्बे तथा नगर-नगर में घर-घर तक लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हुए पेयजल प्रबंधन में जनसेवा की नई मिसाल कायम की है। राज्य सरकार के दो सालों का यह कार्यकाल जलदाय विभाग के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। सरकार के पहले साल में वर्ष 2019 की गर्मियों के मौसम सीजन में पेयजल आपूर्ति सप्लाई को लेकर विभाग के सामने कई विकट चुनौतियां थी। मानसून और वर्षा की स्थिति को लेकर पूरा प्रदेश चिंतित था।

श्री गहलोत के निर्देशन में उन स्थितियों में जलदाय विभाग ने एक के बाद एक महत्त्वपूर्ण फैसले लिए। इन निर्णयों को धरातल पर लागू करने में जलदाय मंत्री डॉ. कल्ला और विभागीय अधिकारियों की टीम ने रात-दिन एक करते हुए कार्य किया। इससे प्रदेश में कहीं भी जनता को पेयजल को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आई और पूरे राज्य में पेयजल का बेहतर प्रबंधन किया। मानसून में देरी की वजह से राज्य के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों का आंकलन कर विभाग द्वारा नलकूपों की स्वीकृति तथा कंटीजेंसी प्लान बनाकर निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए समय पर कदम बढ़ाए गए। इसके अलावा पाली में रेल के माध्यम से पानी पहुंचाया गया।

सरकार के दूसरे साल में भी गर्मियों के सीजन को लेकर जलदाय विभाग ने काफी पहले से तैयारी कर ली थी। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति से काफी पहले ही फरवरी माह में ही सभी जिला कलक्टर्स को कंटीजेंसी प्लान के तहत 50-50 लाख की राशि स्वीकृति की गई। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर्स के माध्यम से जल परिवहन के लिए 65 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए। मुख्यमंत्री ने कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने विकट स्थितियों में स्वयं अग्रिम मोर्चे पर कमान सम्भाली।

श्री गहलोत ने शासन में संवेदनशीलता और जवाबदेही के अपने संकल्प के अनुरूप लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सभी विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद किया। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई की स्थिति और आवश्यकताओं की निरंतर समीक्षा करते हुए सभी विधायकों को विशेष तौर पर 25-25 लाख रुपये के कार्य अपने क्षेत्रों के लिए कराने की भी मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए ऐसे ही त्वरित, सामयिक एवं समयबद्ध निर्णयों और जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की समयबद्ध मॉनिटरिंग से विभाग ने प्रदेश के सभी हिस्सों में निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जिम्मेदारी का सतत् रूप से बखूबी निर्वहन किया है।

घरेलू कनेक्शनों पर 15 हजार लीटर तक के उपभोग पर जल शुल्क माफ

मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष में राज्य के घरेलू पेयजल उपभोक्ताओं को बिलों पर देय पेयजल शुल्क में संशोधन कर चालू मीटर वाले घरेलू कनेक्शनों पर प्रतिमाह 15000 लीटर तक जल उपभोग करने पर जल शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी है। इसके तहत परियोजनाओं से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में डीडीपी ब्लॉक में 70 लीटर, प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन एवं शेष योजनाओं में 40 लीटर, प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन तक के उपभोग पर जल शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। अन्य ग्रामीण जल योजनाओं में भी जल उपभोग पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। पूरे प्रदेश में अब तक इस छूट से शहरी क्षेत्र के 56 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ 80 लाख आबादी को सीधा लाभ मिला है।

> राज्य सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गांव-ढाणी, कस्बे तथा नगर-नगर में घर-घर तक लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हुए पेयजल प्रबंधन में जनसेवा की नई मिसाल कायम की है।

गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों पर फोकस

जलदाय विभाग द्वारा प्रदेश में गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को लाभान्वित करने पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। राज्य में ऐसी बस्तियों में गत दो सालों में 813 आर.ओ. प्लाण्ट तथा 922 सौर ऊर्जा आधारित डी फ्लोरिडेशन यूनिट स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 5 हजार 339 नये नलकूप तथा 11 हजार 317 नए हैण्डपम्प लगाकर उन्हें चालू किया गया है, जबकि 4 लाख 63 हजार खराब हैण्डपम्पों को भी सुधार कर पुन: चालू किया गया है।

वृहद पेयजल परियोजनाओं से शहर, गांव और ढाणियां लाभान्वित

कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में वृहद पेयजल परियोजनाओं के कामों को भी गति देते हुए जल आपूर्ति तंत्र को मजबूती प्रदान की है। इन मेजर प्रोजेक्ट्स के जरिए सतही जल स्रोत से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 14 शहरों को आंशिक तौर पर तथा 2 हजार 544 ग्राम एवं 2 हजार 497 ढाणियों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित किया गया है। गत दो वर्षों की बात की जाए तो इस दौरान प्रदेश में 9 वृहद पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण करते हुए इनसे जुड़ी आबादी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया गया है।

इन बड़ी परियोजनाओं में बूंदी जिले की इन्द्रगढ़-चाकन पेयजल परियोजना, चम्बल-बून्दी कलस्टर परियोजना (विस्तार चम्बल-भीलवाडा परियोजना), कोटा जिले की बोरावास-पदमपुरा पेयजल परियोजना, बारां जिले की अटरू-शेरगढ़ पेयजल परियोजना, प्रतापगढ़ शहर की विद्यमान पेयजल सप्लाई योजना के पुनर्गठन का कार्य, जयपुर शहर के लिए जयपुर-बीसलपुर पेयजल परियोजना (खो-नागोरियन), बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ की 344 ग्रामों की पेयजल परियोजना, झालावाड़ जिले में राजगढ़ पेयजल परियोजना एवं जोधपुर जिले की पांचला-घेवरा चिराई क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना शामिल है। जलदाय विभाग ने उक्त सभी मेजर प्रोजेक्ट्स के कार्यों को मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पूरा कर इन क्षेत्रों की जनता को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया है। इसके अलावा विभाग की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रदेश में 16 वृहद् पेयजल परियोजनाओं के निर्माण तथा 27 वृहद पेयजल परियोजनाओं की डीपीआर बनाने की स्वीकृति दी गई है। इनके माध्यम से राज्य के अलग-अलग जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जल कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे।

गुलाबी नगर में बीसलपुर पानी के लिए 853 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जून, 2020 में गुलाबी नगरवासियों को 853 करोड़ रुपये की लागत वाले दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना फेज-प्रथम, स्टेज-2 तथा बीसलपुर-पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज-प्रथम, स्टेज-प्रथम का शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी। जयपुर शहर की बढ़ी हुई पेयजल मांग एवं आगामी दिनों में बढ़ने वाली मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दीर्घकालीन प्रस्ताव केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजे हैं।

केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित इन प्रस्तावों के बीच जयपुर शहर में पेयजल की बढ़ी हुई मांग के मद्देनजर राज्य सरकार ने अपने स्तर पर तत्काल कदम उठाते हुए 288.90 करोड़ रुपये की बीसलपुर परियोजना फेज-प्रथम स्टेज-2 को स्वीकृति प्रदान की। इससे जयपुर शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों को 170 एमएलडी अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध होगा। इस परियोजना के कार्य के लिए 173.16 करोड़ की राशि का कार्य अक्टूबर, 2022 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार जयपुर में पृथ्वीराज नगर के लोगों की सुचारू पेयजल व्यवस्था की मांग के सम्बंध में जलदाय विभाग द्वारा बीसलपुर बांध से 170 एमएलडी अतिरिक्त पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के बाद इस क्षेत्र के लिए 563.93 करोड़ रुपये की परियोजना को भी स्वीकृत किया गया है। इससे योजना से 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित होगा एवं पृथ्वीराज नगर क्षेत्रवासियों को अक्टूबर, 2022 तक पेयजल उपलब्ध होगा। 295.51 करोड़ रुपये की परियोजना का कार्य भी अक्टूबर, 2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

राजस्थान विश्वविद्यालय को भी बीसलपुर का पानी

जलदाय विभाग ने जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों को बीसलपुर पेयजल परियोजना से जोडने के लिए 15.60 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति योजना तैयार की। इसके लिए 7.05 करोड़ रुपये का कार्यादेश जारी किया गया। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस परियोजना का शिलान्यास किया। इस योजना से राजस्थान विश्वविद्यालय और इससे जुड़े महाराजा एवं महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज एवं पोद्दार प्रबंधन संस्थान

> राज्य के घरेलू पेयजल उपभोक्ताओं को बिलों पर देय पेयजल शुल्क में संशोधन कर चालू मीटर वाले घरेलू कनेक्शनों पर प्रतिमाह 15000 लीटर तक जल उपभोग करने पर जल शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी है।

को प्रतिदिन 27 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। इन स्थानों पर अभी टयूबवैल से आपूर्ति की जा रही है। गिरते भू-जल स्तर एवं पानी की गुणवत्ता को लेकर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों ने इस योजना के लिए मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल और निर्देश के बाद मंजूर किया गया। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय परिसर और महारानी कॉलेज में एक-एक स्वच्छ जलाशय और एक-एक उच्च जलाशय का निर्माण किया जायेगा। साथ ही द्वितीय चरण में 10 लाख लीटर क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किए जाने की योजना है, जिसके उपचारित जल से बागवानी, सफाई और अन्य कार्य हो सकेंगे। योजना का कार्य अक्टूबर, 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जोधपुर व पाली के लिए 1454 करोड़ रुपये की परियोजना

जोधुपर एवं पाली जिले के 5 शहर एवं 2 हजार 04 गांवों की आबादी के लिए वर्ष 2 हजार 51 तक की जरूरतों का आंकलन करते हुए जलदाय विभाग द्वारा 1454.00 करोड़ रुपये की लागत वाली महत्त्वाकांक्षी योजना 'राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज-3' तैयार की गई है। इस योजना पर वित्त विभाग द्वारा सहमति जारी कर दी गई। इसके बाद बाह्य एजेन्सी ''जायका'' से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव आर्थिक मामलात विभाग, भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

जल जीवन मिशन में घर-घर नल कनेक्शन

गत दो सालों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत घर-घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य के तहत जलदाय विभाग द्वारा अब तक 8 हजार 261 करोड़ की राशि की स्वीकृतियां केन्द्र और राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत के हिस्से के आधार पर जारी की जा चुकी है। इसमें 555 एकल परियोजनाएं, 15 पूर्ण/प्रगतिशील वृहद एवं एक नवीन परियोजना शामिल है। इन स्वीकृत योजनाओं से लगभग 11.56 लाख परिवारों को घर-घर नल कनेक्शन देते हुए स्वच्छ पेयजल सुलभ कराया जाएगा। कोविड-19 के कारण विषम आर्थिक स्थितियों और केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 से पहले राज्य में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मिलने वाली 90 प्रतिशत की सहायता को कम करके 50 प्रतिशत किए जाने के बावजूद प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यो को राज्य सरकार द्वारा गति दी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य की विषम भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर पेयजल परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत के स्थान पर केन्द्र शासित प्रदेशों और पहाड़ी क्षेत्रों के बराबर 90 प्रतिशत का हिस्सा केन्द्र सरकार से दिलाने का आग्रह किया है।

जलदाय मंत्री डॉ. कल्ला ने भी केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष राज्यों के जलदाय मंत्रियों की बैठक और सम्मेलनों में बार-बार राज्य सरकार की इस मांग को दोहराया कि केन्द्र सरकार वर्ष 2013 से पहले की तरह पेयजल परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत अनुदान को बहाल करे। प्रदेश में घर-घर में जल सम्बन्ध देने के लिए जलदाय विभाग की नीति में परिवर्तन भी किया गया है। पहले प्रदेश में केवल 4000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में पेयजल कनेक्शन देने का प्रावधान था, इस सीमा को समाप्त कर अब नई नीति के अनुसार प्रत्येक घर को पेयजल कनेक्शन दिया जा रहा है।

नवाचार एवं अभिनव प्रयोग

राज्य में पहले पीने के पानी में जीवाणु परीक्षण प्रचलित तरीके से हाईड्रोजन सल्फाइड द्वारा किया जाता था। इस पद्धति से जांच के परिणाम 48 घंटों बाद उपलब्ध हो पाते थे। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जलदाय विभाग के तहत जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (डब्ल्यूएसएसओ-वाटर एंड सेनिटेशन सपोर्ट आर्गेनाईजेशन) द्वारा जयपुर स्थित मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी के साथ अनुसंधान करते हुए पीने के पानी में जीवाणु परीक्षण के लिए सुविधा विकसित की गई है। इस के माध्यम से अब जीवाणु परीक्षण का परिणाम मात्र 8 से 10 घंटे में उपलब्ध हो जाता है। इस पहल से समुदाय एवं अधिकारियों द्वारा पीने के पानी का परीक्षण कम अवधि में करते हुए सुधार की प्रक्रिया को जल्द अपनाना सम्भव हो गया है।

विभाग द्वारा पूरे प्रदेश की 11 हजार 325 ग्राम पंचायतों में जल प्रबन्धन में जनता के सहयोग एवं भागीदारी की प्रवृति को बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) के माध्यम से एक जन जागृति अभियान भी संचालित किया गया। जनवरी, 2020 में सम्पन्न इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम में जल चेतना रथ, ग्रामीण सहभागिता आंकलन व ग्राम जल मेलों द्वारा आम जनता को जागरूक किया गया। सरकार के दो वर्षो के कार्यकाल के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं राजस्थान सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट (रेसवार्म) को साउथ आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा नई दिल्ली में 2019 में आयोजित सीआईआई त्रिवेणी जल सम्मेलन में एप्रिशियेसन अवार्ड भी प्रदान किया गया।

कोरोनाकाल की गर्मियों में समुचित जल प्रबंधन

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2020 में कोरानाकाल और गर्मियों के सीजन में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल परिवहन (टीओडब्ल्यू-ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर) की व्यवस्था के लिए अप्रेल, 2020 से जुलाई, 2020 की अवधि के लिए 65 करोड़ 12 लाख 93 हजार रुपये की स्वीकृति जारी की गई। सभी जिला कलक्टर्स को कंटीजेंसी प्लान के तहत 50-50 लाख रुपये दिए गए, साथ ही जिलों से आवश्यकता के अनुसार इस धनराशि के अतिरिक्त भीप पेयजल प्रबंधन के लिए प्रस्ताव प्राप्त कर समय पर स्वीकृतियां जारी कर राज्य की जनता को राहत प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विधायकों को कोरोनाकाल और गर्मियों को देखते हुए 25-25 लाख रुपये की स्वीकृति भी विशेष तौर पर जारी करने की अनुमति प्रदान की। इसके तहत 33 जिलों में 44 करोड़ 67 लाख 17 हजार रुपये की राशि के 1073 कार्य स्वीकृत किए गए। इस दौरान जलदाय विभाग द्वारा प्रदेश में पेयजल की समस्या वाले भागों में ग्रामीण क्षेत्र में 2 हजार 586 गांव एवं 3 हजार 739 ढाणियों में 1458 टैंकर्स से प्रतिदिन 5916 ट्रिप के आधार पर जल परिवहन कर लोगों को उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 52 कस्बों में 570 टैंकर्स के माध्यम से 3 हजार 898 ट्रिप प्रतिदिन के आधार पर जल परिवहन करते हुए लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कर लाभान्वित किया गया।

'लॉकडाउन' में नियमित पेयजल आपूर्ति पर पूरा फोकस

कोराना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए घोषित 'लॉकडाउन' की अवधि में प्रदेश में जलदाय विभाग के कार्मिकों ने जनता को पेयजल की निर्बाध और समयबद्ध आपूर्ति के लिए 'कोरोना वारियर्स' के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई। कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए पीपीई किट पहनकर लीकेज की मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्यों को समय पर सम्पादित किया। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में पेयजल की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए फील्ड में कार्य कर रहे जलदाय विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी तकनीकी एवं संविदा कार्मिकों के इस जज्बे की बहुत सराहना हुई है। साथ ही निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल की सप्लाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, इसके लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में राज्य स्तर के साथ ही सभी जिलों में 'कंट्रोल रूम' बनाए गए। इन सभी कंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे लगातार उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करते हुए उनकी समस्याओं और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया गया। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया और इस व्यवस्था के बारे में दिन-प्रतिदिन रिपोर्ट लेते

"उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पानी का कनेक्शन देने के लिए राजनीर पोर्टल पर विकसित एप का शुभारम्भ किया गया। जल कनेक्शन के लिए 'ऑनलाइन एप' के प्रारम्भ होने से अब जल उपभोक्ताओं को सुगमता से घर बैठे पानी के कनेक्शन की सुविधा मिलना आरम्भ हो गई है।"

हुए अभाव अभियोग निराकरण को पूरी तवज्जो दी। लॉकडाउन अवधि में जनता को हुई दिक्कतों के मद्देनजर जलदाय विभाग द्वारा मार्च, 2020 के जल राजस्व बिलों की देय तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लेकर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत प्रदान की गई। साथ ही राज्य सरकार ने विभाग के तहत घर-घर वसूली और नीलामी कार्यक्रम को भी कोरोना के कारण लॉकडाउन की अवधि में स्थगित कर लोगों को लाभान्वित किया गया।

हैंडपम्प मरम्मत अभियान

प्रदेश में अप्रेल 2020 से संचालित 44वें हैंडपम्प मरम्मत अभियान में ग्रामीण क्षेत्र में अब तक एक लाख 41 हजार 184 हैंडपम्पों एवं शहरी क्षेत्रों में 19 हजार 889 हैंडपम्पों की मरम्मत की गई है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2019-2020 में संचालित 43वें हैंडपम्प अभियान में भी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख 11 हजार 302 हैंडपम्पों एवं शहरी क्षेत्रों में 32 हजार 147 हैंडपम्पों की मरम्मत की गई।

ऑनलाइन पेयजल कनेक्शन की सौगात

जलदाय मंत्री डॉ. कल्ला ने अक्टूबर, 2020 में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पानी का कनेक्शन देने के लिए राजनीर पोर्टल पर विकसित एप का शुभारम्भ किया गया। जल कनेक्शन के लिए 'ऑनलाइन एप' के प्रारम्भ होने से अब जल उपभोक्ताओं को सुगमता से घर बैठे पानी के कनेक्शन की सुविधा मिलना आरम्भ हो गई है। इस 'एप' की लॉचिंग से पेयजल उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगाने की दिक्कत से निजात मिलेगी। एप द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारम्भ में जयपुर में जगतपुरा और विद्याधर नगर क्षेत्र के निवासियों को मिल रही है। आगामी दिनों में इस सुविधा का जयपुर शहर में विस्तार किया जाएगा, फिर चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू होगी। सरकार के जन घोषणा पत्र में डोर स्टेप डिलीवरी के तहत घोषणा के बारे में जलदाय विभाग ने नये जल सम्बन्धों को जारी करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के साथ मिलकर यह एप तैयार किया है। ●

मनमोहन हर्ष

श्रीगंगानगर

सुमन व संतोष बनी आत्मनिर्भर

राज्य सरकार की योजनाओं से युवाओं को मिला रोजगार

राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य में पढ़ा-लिखा युवा वर्ग सरकारी नौकरी की तलाश में कई बार भटकता रहता है, परन्तु सभी का चयन सरकारी नौकरी में हो जाये, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रदेश के विकास के लिये युवाओं का अपने पैरों पर खड़े होना अत्यधिक आवश्यक है। युवा वर्ग को स्वरोजगार व प्राईवेट सेक्टर में भी मनपंसद कार्य करने का मौका देने के लिहाज से राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रदेश के युवाओं को एम्पलॉयमेंट लिंकड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आरएसटीपी, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना आदि में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन योजनाओं से प्रतिवर्ष बेरोजगार युवाओं को विभिन्न सैक्टर्स में रोज़गार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

श्रीगंगानगर जिले में आरएसटीपी (रेग्युलर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम) के तहत ब्राईडल मेकअप आर्टिस्ट के दो सेन्टर चलाये जा रहे हैं। इसी प्रकार का एक सेन्टर अनूपगढ़ में भी चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत साल में 150 से अधिक ब्राईडल मेकअप आर्टिस्ट प्रशिक्षण लेते हैं। महिला वर्ग में इस योजना से बेहद लाभ हो रहा है। महिलाएं शादी के बाद कई बार आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती हैं तथा परिवार को मजबूती देने का उनका सपना अधूरा रह जाता है। परन्तु इस योजना द्वारा महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। योजना में महिलाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। तीन महीने में ही व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर महिला स्वयं का रोजगार आरम्भ कर लेती है। लघु बजट से ब्यूटी पार्लर योजना या स्वरोजगार संभव हो जाता है अथवा किसी भी सैलून में जॉब आसानी से मिल जाती है।

राजस्थान आजीविका कौशल विकास योजना के तहत सुमन व संतोष को ब्राईडल मेकअप आर्टिस्ट का प्रशिक्षण दिया गया। सुमन हिन्दी में एमए तथा संतोष पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए है। वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद दोनों ही सरकारी नौकरी पाने में विफल रही। दोनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया व आज लघु बजट से घर पर ही अपना पार्लर चला रही हैं।

जिला कलक्टर ने इन दोनों महिलाओं से मुलाकात की व कार्य के प्रति समर्पण को देखते हुए भविष्य में ऋण उपलब्ध करवाने के लिये मदद का वादा किया। उन्होंने जिला उधोग केन्द्र के महाप्रबंधक को इन महिलाओं को ऋण देने के लिये निर्देशित किया। जिला कलक्टर महिलाओं के जज़्बे से प्रभावित हुए। युवाओं को इसी प्रकार आत्मनिर्भर बन प्रदेश के विकास में सहयोग करना चाहिए। सुमन व संतोष के सपनों की उड़ान अभी बाकी है। वे एंटरप्रेन्योर बनकर अपने परिवार को सुखद भविष्य देना चाहती है। ●

ऋतु सोढ़ी

बूंदी

कोविड-19 नियंत्रण व टीकाकरण में बूंदी अग्रणी

टीकाकरण में 108.72% उपलब्धि

कोरोना महामारी ने विश्व स्तर पर व्यापक प्रहार किया। संक्रमण की भयावहता ने जनजीवन को हिला कर रख दिया, लेकिन बूंदी जिला इन विकट परिस्थितियों के बीच भी सुदृढ़ होकर सुरक्षित बना रहा। एक ओर राज्य सरकार के कुशल निर्देशन में गाइडलाइन की सख्ती से पालना और दूसरी ओर आमजन को जागरुकता का पाठ पढ़ाते हुए जिला प्रशासन ने इस महामारी को यहां हावी होने से रोके रखा। अब वैक्सीनेशन के साथ बूंदी प्रबंधन और जागरूकता के बलबूते स्वस्थ बना हुआ है।

कोरोना संक्रमण काल में यहां एक साथ कई मोर्चों पर कार्य हुए। एक ओर संक्रमण बचाव के उपायों की पालना, संक्रमितों का प्रबंधन, पीड़ित एवं आमजन को आवश्यक सेवाओं व सुविधाओं की आपूर्ति वहीं दूसरी ओर जागरुकता का गांव-गांव, ढाणी-ढाणी बिगुल बजाना।

राज्य सरकार की प्रभावी निगरानी एवं मार्गदर्शन में इन सभी पक्षों पर मजबूती से कार्य हुआ। नतीजन वर्ष 2021 आते-आते कोरोना कमजोर पड़ता गया। जनवरी अंत से भर्ती मरीजों की संख्या कम होती रही और नए संक्रमितों की संख्या भी अब नगण्य रह गई है।

वर्तमान में यहां 3 हजार 493 व्यक्ति पॉजिटिव से निगेटिव हो चुके हैं। पोस्ट कोविड व्यवस्थाएं भी प्रभावी रूप से संचालित है। कोविड संक्रमण से मुक्त हुए व्यक्तियों की समुचित देखभाल और परामर्श के लिए पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाया गया है जहां एक छत

के नीचे आयुर्वेद, योग, होम्योपेथी, यूनानी चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है।

टीकाकरण में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि

जिले में कारोना वैक्सीन के आरंभिक चरणों में भी बूंदी की सफलता उल्लेखनीय रही। जिला कलक्टर के निर्देशन में टीकाकरण अभियान के पूर्व से ही जागरूकता एवं प्रोत्साहन पर विशेष जोर दिया गया जिसके सुपरिणाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए हुए टीकाकरण में बूंदी प्रदेश में अग्रणी रहा है। टीकाकरण की शुरूआत जिला कलक्टर ने टीका लगवाकर की।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस चरण में भी बूंदी की उपलब्धि 97.2 प्रतिशत रही है। पुलिस टीकाकरण में 95.58 फीसदी उपलब्धि रही। जिला परिषद कार्मिकों ने उत्साह से टीकाकरण कराते हुए उपलब्धि प्रतिशत को 112.82 तक पहुंचा दिया।

इस प्रकार बूंदी में 111 साइट्स पर 10 हजार 113 के लक्ष्य के विरुद्ध 10 हजार 995 व्यक्ति टीकाकरण करा चुके हैं। समग्र उपलब्धि 108.72 फीसदी रही प्रतिशत रही है। वेक्सीनेशन के बाद सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं।

रचना शर्मा

झालावाड़

संतरा उत्पादन में झालावाड़ बना मिसाल

झालावाड़ को संतरा उत्पादन में जिन प्रगतिशील किसानों की वजह से छोटा नागपुर कहा जाता है उनमें अग्रणी प्रगतिशील किसान है झालावाड़ मुख्यालय से 65 किमी दूर पिड़ावा तहसील के सरोनिया गांव निवासी श्री द्वारकालाल पाटीदार।

संतरा उत्पादक श्री लाल बताते हैं कि उनके संतरे की गुणवत्ता के कारण व्यापारी फसल तैयार होने से पहले ही बगीचे में मोल भाव कर लेते हैं। इससे बाजार-मण्डी में बिना जाए ही घर बैठे अपनी फसल के अच्छे दाम मिल जाते हैं। गत वर्ष ही उन्हें 70 बीघा (17 हैक्टयर) में लगाए गए संतरे के 5200 पौधों से 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से फल बेचने पर 83 लाख रुपए की आय हुई है। इस वर्ष संतरा के 40 रुपए प्रति किलो के भाव लगे हैं।

साधारण कृषक परिवार में जन्मे 9वीं कक्षा तक शिक्षित श्री लाल ने 18 वर्ष की आयु में अपने खेतों में क्षेत्र के अन्य किसानों की तरह ही सोयाबीन, धनिया, मसूर, मक्का, गेहूं जैसी परम्परागत फसलें उगाना शुरू किया। कठोर मेहनत के बावजूद वे अपनी पथरीली भूमि में कृषि कार्य से अपेक्षानुरूप नहीं कमा पाते थे। परम्परागत फसलें कभी तो प्रकृति के कोप का भाजन बन जाती थी तो कभी बाजार भाव अपेक्षा से कम मिलते थे।

वर्ष 2005-06 में श्री लाल कृषि विज्ञान केन्द्र, झालावाड़ के कृषि वैज्ञानिकों के सम्पर्क में आए। यहां उन्हें संतरा उत्पादन के लाभों से अवगत कराया गया। किसान श्री लाल द्वारा वर्ष 1995-96 में लगाए गए बगीचे से हुई 2 लाख रुपए की आमदनी से उत्साहित होकर वर्ष 2007 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के सहयोग से अपने खेत में 1000 पौधों का बगीचा स्थापित किया।

साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र, झालावाड़ में नियमित रूप से दिए जा रहे कृषि एवं उद्यानिकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर संतरे के उत्पादन की नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों को जाना एवं उन्हें धरातल पर उतारा।

वैज्ञानिक सलाह से समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन द्वारा रोग व कीटों की रोकथाम और मशीनीकरण से बगीचे को उद्योग की तरह पालते हुए 1000 पौधों से पांचवे वर्ष में 20 लाख 51 हजार रुपए की आय प्राप्त कर इस किसान ने कृषि वैज्ञानिकों के सामने चौकाने वाला उदाहरण पेश किया क्योंकि आमतौर पर 6-7 वर्ष बाद ही संतरा का फल पेड़ों में आना शुरू होता है।

कृषि विज्ञान केन्द्र में दिए गए तकनीकी ज्ञान एवं उद्यान विभाग के सहयोग से किए गए नवाचार द्वारा संतरे के गुणवत्तात्मक एवं

मात्रात्मक उत्पादन में अभिवृद्धि हुई।

संतरा उत्पादन के लिए किए नवाचार

पानी की कमी को पूरा करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई 70 से 80 प्रतिशत बचत वाली बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली अपनाई जिससे वे कम पानी से ही बगीचे के क्षेत्र में वृद्धि कर पाए।

पॉवर स्प्रेयर बनाया

संतरों के पेड़ बड़े होने के कारण पीठ पर लटकाकर छिड़काव करने वाली मशीन से दवा का छिड़काव करना असंभव था। संतरे के ऊंचे पेड़ों पर दवा का छिड़काव करने के लिए उन्होंने जुगाड़ कर शक्तिचलित छिड़काव मशीन बनाई। इस मशीन की सहायता से वे एक दिन में संतरे के 1000 पेड़ों पर बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सफलता पूर्वक एक समान रूप से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। समय-समय पर वैज्ञानिक सलाह पाकर कीट प्रबंधन पर होने वाली कृषिगत लागत में भी कटौती की जा रही हैं।

संतरा तुड़ाई उपरांत सिकेटियर की मदद से कटाई छटाई कर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड (Copper Oxi Chloride) 2.0 ग्राम एवं डाईमिथोएट 1.5 मिली लीटर से छिडकाव (अप्रेल, अगस्त एवं दिसम्बर माह में दो बार में किया जाता है जिसे 4, 8, 12 के नाम से भी जाना जाता है) किया तो काली मस्सी रोग मुक्त बगीचा बन गया।

छाल बेधक कीट से बचाव के लिए द्वारकालाल ने पौधों में चूना और नीला थोथा 1-1 किलो को 10 लीटर पानी के साथ बोर्डो पेस्ट बनाकर पौधों के तने की तीन फीट तक पुताई की।

गर्मी के दिनों में हकाई-जुताई कर 80 से 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट खाद, NPK 12-32-16 उर्वरक 500 ग्राम प्रति पौधा गोलाकार रूप में 5 फीट रिंग बनाकर दिया तो

पौधों में जुलाई के पहले सप्ताह में अच्छी फूटन के साथ फूल आ गए। उन्होंने फूटन देखकर उसी समय स्वयं की स्प्रे मशीन से ईमीडाक्लोरपिट 0.5 एम.एल. व फफूंदनाशक कार्बनडाजिम 2 ग्राम लीटर एवं प्लेनोफ्क्सि दवाई का छिडकाव किया और दाने बनने पर NPK (18-18-18) 5 ग्राम प्रति लीटर व मेंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर व जिब्रेलिक अम्ल 10 PPM का छिडकाव किया। फल नीबू आकार के होने पर सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जलघुलनशील उर्वरक का छिडकाव करते हैं, तो फल चमकदार व अच्छी गुणवत्ता वाले प्राप्त होने के साथ उनका बाजार भाव भी अच्छा मिलता है।

राजस्थान सरकार ने श्री द्वारकालाल को उद्यानिकी की नई तकनीकों को जानने के लिए इजरायल भेजा। जहां उन्होंने पौधों के तनों पर मिट्टी चढ़ाना और समय-समय पर दवा का स्प्रे करना सीखा। कृषि में वैज्ञानिक सलाह को अपनाकर किए गए नवाचारों के कारण कृषि विभाग द्वारा कृषि वैज्ञानिक का दर्जा कई गांवों में एचआईटीसी जयपुर द्वारा सैकड़ों किसानों को ट्रेनिंग दी है। बहुत से किसान एवं कृषि वैज्ञानिक उनके खेत का भ्रमण करने आते हैं। किसान श्री लाल को संतरा उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए कई सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है।

उनसे प्रभावित होकर करीब 50 से 60 किसानों ने अपने खेतों में परम्परागत खेती के स्थान पर संतरा उत्पादन को बढ़ावा दिया है जिससे दूसरे किसानों को भी संतरा उत्पादन से अच्छी आमदनी होने लगी है। पूरा गांव संतरा के उत्पादन में रोल मॉडल बनकर उभरा है। ●

हेमन्त सिंह

सीकर

जिले में 20 मदरसों को कम्प्यूटर, 9 मदरसों में स्मार्ट क्लास के लिए डयूल डेस्क उपलब्ध करवाई

मदरसा आधुनिकीकरण योजना

सीकर जिले में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसा शिक्षा को स्कूलों की तरह आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए 20 मदरसों को कम्प्यूटर, 9 मदरसों में स्मार्ट क्लास एवं छात्र-छात्राओं को बैठने के लिए डयूल डेस्क उपलब्ध करवाई गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि माण्डेला छोटा (फतेहपुर) में 15 लाख रूपये की लागत से मदरसा भवन का निर्माण करवाया जायेगा जिसमें अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जायेगा। छात्रवृति योजना में अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी) समुदाय के निम्न आय वर्ग के छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृति प्रदान की जा रही है। इसमें अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पोस्ट मैट्रिक मेरिट, मैरिट कम मीन्स एवं अनुप्रति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी जा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के बालक वर्ग के लिए सीकर जिला मुख्यालय एवं फतेहपुर में छात्रावास निर्माण के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है।

अल्पसंख्यक व्यवसाय व शिक्षा ऋण के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अल्संख्यक वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए 153 व्यक्तियों को व्यवसाय ऋण एवं शिक्षा प्राप्त करने वाले 18 छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इसी प्रकार कौशल विकास प्रशिक्षण के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है ताकि स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके। पन्नालाल चितलांगिया रा.उ.मा.वि. में सीकर में 38 लाख 68 हजार रुपये की लागत से चार कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाया गया है तथा मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना में मदरसा इस्लाउल बनात किरडोली में 10 लाख रूपये की लागत से भवन निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ●

विकास ने राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में रहकर की पढ़ाई, चिकित्सक बनने का सपना हुआ साकार

विकास कुमार वर्मा पुत्र सुरेश कुमार वर्मा, कारंगा छोटा फतेहपुर शेखावाटी, सीकर के रहने वाले है। विकास ने बताया कि पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के कारण नियमित रूप से अध्ययन कर पाना उसके लिये मुश्किल था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर द्वारा संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फतेहपुर के बारे में उसे जानकारी मिली। छात्रावास में नि:शुल्क आवास एवं भोजन व्यवस्था की जाती है। छात्रावास में प्रवेश से वह अध्ययन कर पाया। वर्ष 2018-19 मे छात्रावास में आवासरत रहते हुये 12वीं कक्षा में 87 प्रतिशत अंक हासिल किये। पढ़ाई नियमित जारी रही। 2020 में आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 97.47 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, जिसकी वजह से उसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता व गुरुजनों के साथ राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर को देते हुए राजकीय अम्बेडकर छात्रावास फतेहपुर शेखावाटी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि राजकीय अम्बेडकर छात्रावास फतेहपुर मे प्रवेश मिलने से वह आगे पढ़ पाया और चिकित्सक बनने का उसका सपना साकार हुआ। ●

पूरण मल

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए

प्रत्येक मतदाता की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी आवश्यक

25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन विभाग राजस्थान की ओर से 11 वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस ऑनलाइन आयोजित किया गया। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रत्येक मतदाता की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी आवश्यक है । मतदाता जागरूक बनें और देश को विकास के पथ पर ले जाने वाले जनप्रतिनिधियों का चयन अपने विवेक के आधार पर करें। इसी अवधारणा को लेकर जयपुर सचिवालय के सभागार में आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने लोगों का आह्वान किया कि लोकतंत्र में प्रत्येक मत का महत्त्व होता है । ऐसे में प्रत्येक मतदाता का यह कर्तव्य है कि वे जागरूक बनें और सोच समझकर मतदान करते हुए ऐसे जनप्रतिनिधियों का चयन करें जो विकास के रास्ते पर देश और समाज को आगे ले जा सके ।

स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण और उसकी मजबूती के लिए प्रत्येक मतदाता की निर्वाचन में सहभागिता आवश्यक है । कोई मतदाता ना छूटे इस अवधारणा के अनुरूप भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक मतदाता को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने की पहल की है और भारत का आम आदमी ही वह शक्ति है जो संविधान के द्वारा दी गई मतदान की शक्ति को प्रयोग करते हुए स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाता है ।

तमाम राजनीतिक दल, उम्मीदवार और नागरिकों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की यह कोशिश रहती है कि वह निर्वाचन प्रक्रिया को न केवल सुगम बनाए बल्कि अपनी तमाम डिजिटल प्रविधियां और तकनीकी पहल से प्रत्येक मतदाता की सहभागिता को सुनिश्चित करें ।

आम आदमी द्वारा उपयोग में ली जाने वाली तकनीक और विविध मोबाइल ऐप की जानकारी जब तक आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी तब तक वे मतदान की प्रक्रिया में अपना हिस्सा नहीं जोड़ सकेंगे । इसी उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा का राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश की जनता के नाम संदेश भी प्रसारित किया गया । आम आदमी की सहभागिता से ही देश को एक अभिनव पहचान मिल सकती है ।

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री प्रेम मेहरा ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि कोरोनावायरस की महामारी के दौर में बीते 1 साल में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्देशित की गई तमाम गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मतदान प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण तरीके से सफल एवं जागरूकतापूर्वक संपन्न करवाया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े तमाम लोग और मशीनरी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हाल ही के विविध चुनावों में अपनी भूमिका को नई पहचान दी है ।

2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत और व्यापक स्तर पर स्वीप गतिविधियों के आयोजन के कारण अब मतदाता पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक, सशक्त एवं सतर्क हुए हैं । इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि सभी मतदाता अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, जागरूक होकर सुरक्षित महसूस करते हुए, मतदान कर सकें यही लोकतंत्र की सफलता की सच्ची कसौटी है।

मतदाताओं को मतदान के महत्त्व के प्रति जागरूक करने के लिए सभी कार्यालयों में मतदाता जागरुकता फोरम स्थापित किए गए हैं। साथ ही शहरी मतदाताओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के क्रम में मतदाता साक्षरता क्लबों को और अधिक सक्रियता से कार्य करना होगा। निर्वाचन विभाग, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम ''सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक'' रखी गयी है ।

भारत निर्वाचन आयोग के नवाचारों के क्रम में 25 जनवरी, 2021 से सभी मतदाताओं के लिए डिजिटल प्रविधियों का शुभारंभ किया गया है । जिसमें से एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ई- एपिक कार्ड है । इसके माध्यम से कोई भी आम मतदाता एप डाउनलोड कर ई - एपिक कार्ड से मतदान की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकता है। यूनिक मोबाइल नंबर दर्ज करवाने के पश्चात आम आदमी अपना एपिक कार्ड लेकर उसे चुनावों में प्रयुक्त कर सकता है ।

भारत निर्वाचन आयोग ने इस अवसर पर वोटर्स की सुविधा के लिए 'हेलो वोटर्स' वेब रेडियो का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने ''हम हैं सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक'' पोस्टर का विमोचन भी किया तथा सभी मतदाताओं को शपथ भी दिलवाई। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने संविधान की उद्देशिका तथा मूल कर्तव्यों का वाचन किया और कहा कि सभी को इनकी मूल भावनाओं को समझने की जरूरत है। कार्यक्रम में निर्वाचन विभाग के ब्रांड एंबेसडर एवं पैरा ओलंपिक विजेता देवेंद्र झाझरिया , अपूर्वी चंदेला ने हेलो वेब रेडियो के लिए शुभकामनाएं दीं। ●

डॉ. सुधीर सोनी

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

कोरोना वैक्सीन इस प्रकार लगेगी:-

1. वैक्सीन के लिए कोविन (Co-WIN) नामक एप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
2. पंजीकरण के लिए दस्तावेज:

   फोटो के साथ आधार / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आई.डी. / पैन कार्ड / पासपोर्ट / जॉब कार्ड / पेंशन दस्तावेज / मनरेगा कार्ड / बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पास बुक/केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद / विधायक को जारी किए गए आधिकारिक प्रमाण पत्र।
3. वैक्सीनेशन की तिथि, स्थान व समय की सूचना पंजीकृत मोबाइल फोन पर मिलेगी।
4. वैक्सीन प्राथमिकता क्रम

   चिकित्साकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोग।

   इसके बाद आम लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

वैक्सीन प्रोग्राम पूरी तरह सुरक्षित है।
वैक्सीन लगवाएं।
किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से बचें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

#राजस्थान_सतर्क_है

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

आम जन की
समस्याओं के समाधान के लिए
राज्य स्तरीय सहायता व समाधान केन्द्र

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181

- विभागों से संबंधित सहायता व शिकायतों का समाधान
- योजनाओं का सुगम एवं पारदर्शी क्रियान्वयन
- लाभार्थियों हेतु सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना
- कोविड-19 संक्रमित को तुरन्त सहायता पहुंचाना

संवेदनशील, जवाबदेह व पारदर्शी शासन हमारा ध्येय

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 की मदद लें

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा

प्रिय प्रदेशवासियो,

प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ ही 'पहला सुख निरोगी काया' हमारे लिए सर्वोच्च सरोकारों में से एक है। इसी ध्येय से पहले हमने नि:शुल्क दवा योजना तथा नि:शुल्क जाँच योजना शुरू की थी, जो आज भी देश में मिसाल बनी हुई हैं। इसी प्रतिबद्धता के तहत हमने दिसम्बर 2019 में निरोगी राजस्थान अभियान लागू किया। गत 10 महीनों से शानदार कोरोना प्रबंधन किया तथा कोरोना टीकाकरण में भी राज्य को मॉडल बनाएंगे। अब हम 30 जनवरी 2021 से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण को लागू कर रहे हैं। यह एक ऐसी अभिनव पहल है जो प्रदेश की लगभग दो तिहाई आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

राज्य में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के 98 लाख लाभार्थी परिवारों के साथ ही सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के पात्र परिवारों को भी शामिल कर योजना का दायरा बढ़ाते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण में अब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना में वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रुपये का लगभग 80 प्रतिशत (1400 करोड़ रुपये) अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

अब प्रति परिवार सालाना नि:शुल्क उपचार सीमा को बढ़ाकर 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए तथा उपचार के लिए उपलब्ध 1401 पैकेज को बढ़ाकर 1576 किया गया है। सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार तथा गंभीर बीमारियों के लिए 4.50 लाख तक का नि:शुल्क इलाज उपलब्ध होगा। सरकारी के साथ-साथ सम्बद्ध निजी तथा राज्य में स्थित भारत सरकार के चिकित्सालयों में भी नि:शुल्क इलाज मिलेगा। खास बात है कि भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च भी नि:शुल्क पैकेज में शामिल किया गया है। राजस्थान की इस अभिनव योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और जीवन रक्षा के इस मिशन में भागीदार बनें।

शुभकामनाओं सहित,

(अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री)

1.10 करोड़ परिवारों को नि:शुल्क उपचार

प्रतिवर्ष 1400 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन

3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध

राजस्थान की एक और अभिनव पहल जो बनेगी मिसाल

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना

नवीन चरण का शुभारंभ : 30 जनवरी, 2021

इलाज के लिए अपना जन-आधार या आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र साथ लाएं

संपर्क करें : 1800 180 6127 या 181 | www.health.rajasthan.gov.in/abmgrsby

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी । चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, महेन्द्र सोनी द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक- डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा • मैसर्स प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, सी-4, बाईस गोदाम, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'-पृष्ठ संख्या 60, मूल्य 20 रुपये/ 60,000 प्रतियां